

RNI No. : UPHIN/2023/84344 ₹ : 30

# प्रेरणा विचार

जुलाई-2023 (पृष्ठ-36) गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित



संसद का नया भवन  
विशाल और आधुनिकता का मिश्रण





# प्रेरणा चित्रभारती फिल्मोत्सव

विषय :

आजादी का अमृत महोत्सव

भारतीय लोकतंत्र

जनजातीय समाज

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की संस्कृति

पर्यावरण

ग्राम विकास

स्वाधीनता आन्दोलन

भविष्य का भारत

सामाजिक सदुभाव

धर्म एवं अध्यात्म

महिला सशक्तीकरण

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के  
कला एवं मीडिया  
विद्यार्थियों के लिए

वर्ग : वृत्तचित्र - कथा फ़िल्में - डॉक्यु ड्रामा  
अधिकतम समय : 20 मिनट

1,2 एवं 3 दिसम्बर 2023  
स्थान : गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा

नगद पुरस्कार मूल्य  
₹ 200000/-



SCAN TO REGISTER

रजिस्ट्रेशन लिंक - <https://prernasamvad.in/registerforfilms>

नोट - प्रविष्टियों को 05 जून से 05 अक्टूबर 2023 तक भेज सकते हैं।

संपर्क सूत्र : डॉ. यशार्थ मंजुल - +91 9821560373

डॉ. राजीव रंजन - +91 9871650421

[www.prernasamvad.in](http://www.prernasamvad.in) / Prerna media  
email : [prernachitrabharti2023@gmail.com](mailto:prernachitrabharti2023@gmail.com)

कार्यालय - +91 9354133754

## -: इस अंक में :-

04 : संपादकीय

05- पर्यावरण संरक्षण के लिए धन से ज्यादा धुन की जरूरत - डॉ. आशीष कुमार

10 - साक्षात्कार

13 - आत्मनिर्भरता की कहानी

14 - भारत की अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति (रूस-यूक्रेन)  
- डॉ. प्रीता पंवार

16 - गुरु पूर्णिमा : सबके अपने प्रतीक कहीं ध्वज तो कहीं ग्रंथ - रमेश शर्मा

24 - डॉक्यूमेन्ट्री फिल्मों का स्वर्णिम भविष्य  
- आशीष कुमार अंशु

26 - कला (सिनेमा) के क्षेत्र में भारत का अभ्युदय - अथर्व शर्मा

30 : पत्रकारिता जगत में हलचल - मोहित कुमार

32 : मुख्य समाचार

34 : क्या आप जानते हैं ?



6- संसद के नए भवन के साथ इतिहास का निर्माण - अवधेश कुमार



8- इतिहास में गुम चोल एवं अन्य भारतीय राजवंश- प्रणव कुमार



12 - भारत को निहारता विश्व समुदाय-डॉ. अनिल निगम



18 - सेवा परमो धर्म: - प्रशांत त्रिपाठी



20- बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय - डॉ. पूनम कुमारी



22- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस विशेष  
- प्रकाश श्रीवास्तव



28 - फिल्म उद्योग को भा रहा जम्मू कश्मीर - डॉ. विनीत उत्पल

### प्रेरणा विचार

RNI No. : UPHIN/2023/84344

वर्ष-1, अंक -7

संरक्षक  
मधुसूदन दादू

सलाहकार मंडल  
श्री हयाम किशोर, डॉ. अनिल निगम  
प्रो. (डॉ.) हरेन्द्र सिंह

संपादक  
डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

कार्यकारी संपादक  
डॉ. प्रियंका सिंह

प्रबन्ध संपादक  
मोनिका चौहान

समन्वयक संपादक  
पल्लवी सिंह

अध्यक्ष अर्जुन कुमार त्यागी की ओर से मुद्रक/प्रकाशक डॉ. अनिल त्यागी द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा प्रेरणा भवन सी-56/20 सेक्टर-62 नोएडा, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय  
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास, सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा  
दूरभाष : 0120 4565851, ईमेल : prenavichar@gmail.com

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा नोएडा की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा।

संपादक



## संसद का नया भवन : विरासत और आधुनिकता का मिश्रण

भारत में प्रजातन्त्र मात्र एक शासन पद्धति न होकर विचारों एवं संस्कारों का अहम हिस्सा रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र के विकास की यात्रा यहीं से शुरू हुई। आज दुनिया भर की आवाजें एक स्वर में कह रही हैं कि भारत बड़े एवं सार्थक बदलावों के मुहाने पर है। चूंकि ना केवल दुनिया का हर पाँचवाँ व्यक्ति भारतीय है बल्कि भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। अतः सबसे बड़ा लोकतंत्र, डेढ़ अरब लोगों का घर एवं 'वसुधैव कुटुंबकम्' जैसे संस्कारों वाला भारत ही दुनिया का विश्व कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे में भारत में होने वाले बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले होंगे। अतः भारत द्वारा विश्व-कल्याण को केंद्र में रखते हुए सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक निर्णय करने होंगे। ऐसी नीतियाँ निर्मित करनी होंगी कि उपनिवेशवादी शक्तियाँ पुनः मानवता को गुलामी का शिकार ना बना सकें। ऐसी शक्तियाँ आज भी ना केवल विद्यमान हैं अपितु सक्रिय भी हैं। उपनिवेशवादी शक्तियों ने दुनिया को दासता, शोषण, लूटमार, युद्ध एवं मौतों का उपहार दिया। आज दुनिया को उनके षड्यंत्रों से बचने एवं उन्हें नकारने का समय है।

भारतवासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप त्वरित नीति निर्माण हेतु देश को 28 मई 2023 को संसद भवन की नई इमारत मिली है। संसद का कार्य संविधान के अनुरूप नीति निर्माण करना है। इक्कीसवीं शताब्दी में इसके लिए आवश्यक है कि संसद भवन आधुनिक तकनीकों एवं साधनों से युक्त हो। कानून को अंतिम रूप देने में इसकी अहम भूमिका है। कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध एवं वैश्विक मंदी के चलते मात्र ढाई वर्ष में इसका निर्माण होना देश एवं सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करता है। भारत जी-20 की अध्यक्षता के इस कालखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने तथा दुनिया के फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाने की मंशा स्पष्ट करना चाहता है। नए संसद भवन में पुराने 720 के मुकाबले 1272 लोगों के बैठने की एवं अगली शताब्दी तक के विस्तार की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नया संसद भवन 'प्लैटिनम-रेटेड ग्रीन बिल्डिंग' के रूप में स्थापित है, जो पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति भारत के समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह क्षेत्रीय कलाओं, शिल्पों एवं सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करते हुए आधुनिक भारत की जीवंतता और विविधता को निर्बाध रूप से एकीकृत करता है, समावेशिता के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए दिव्यांगजनों को भी प्राथमिकता देता है। संसद की संगीत गैलरी, स्थापत्य गैलरी एवं शिल्प गैलरी भारत की विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करती हैं। साथ ही डिजिटल मतदान तंत्र, सु-अभियांत्रिक ध्वनिकी और अत्याधुनिक दृश्य-श्रव्य यंत्रों एवं तंत्रों की स्थापना की गई है। इसमें जहाँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरणा ली गई है, वहीं सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक 'सेन्गोल' को स्थापित कर सत्ता हस्तांतरण के माध्यम से आजादी के अमर सपनों को प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि भी दी गई है। संसद के नए भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, कला भी है, कौशल भी है, संस्कृति भी है, और संविधान के स्वर भी हैं। इसमें परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है।

संसद के नए भवन के निर्माण में हजारों-लाखों मजदूरों का पसीना लगा हुआ है। अतः आवश्यक है कि नई संसद उन्हें सम्मानयुक्त जीवन देने की प्रेरणा एवं साक्षी बनेगी। यहाँ जनता के प्रतिनिधि भारत केंद्रित नीतियाँ बनाने, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने, विश्व कल्याण हेतु विकसित देश बनाने, नई पीढ़ियों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने, उज्वल भविष्य का आधार बनाने, महिलाओं, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, दिव्यांगों आदि के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण का कार्य करेंगे। अपेक्षा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद भवन की ईंटों, छतों एवं दीवारों के कण-कण से प्रस्फुटित होती राष्ट्र प्रथम एवं गरीब-कल्याण की आवाज को सुन मूर्त रूप दे सकेंगे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ अच्छे भवन एवं इमारत बनाने वाले कारीगरों एवं शिल्पकारों के हाथ काट दिए गए। इसके विपरीत संसद के नए भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों के श्रम को एक डिजिटल गैलरी समर्पित कर उनके योगदान को अमर करते हुए सरकार ने एक अनूठी पहल की है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में 'संसद का यह नया भवन एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत, नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्यपथ पर और सशक्त होकर चलने वाले नये भारत के सृजन का आधार बनेगा।' हर नागरिक की यह अपेक्षा भी होगी कि विपक्ष अपनी हठधर्मिता छोड़ राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखते हुए सकारात्मक भूमिका निभाने के अपने राष्ट्रीय कर्तव्य से विमुख ना हो। अपेक्षित परिणाम पाने के लिए हर भारतीय की ऐसी सरकार चुनने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जो राष्ट्रहित के सम्मुख स्वार्थी तत्वों के व्यक्तिगत कारणों से किए जाने वाले विरोध की चिंता ना करे चाहे वे चुने जनप्रतिनिधि ही क्यों ना हों।

संपादक



# पर्यावरण संरक्षण के लिए धन से ज्यादा धुन की जरूरत



डॉ. आशीष कुमार  
मीडियाविद

बारहमासी हो चुकी जल की समस्या गर्मियों में चरम पर होती है। शहरों के गरीब और मध्यमवर्गीय तबके में बूंद-बूंद के लिए हाहाकार मचा रहता है। बिडंबना तो यह है कि इस विकराल समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। सरकारों के साथ आम जन में भी जल संरक्षण के प्रति संजीदगी दिखाई नहीं देती है। शायद लोगों को लगता है कि उनके प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। जमीन पर लगातार कंक्रीट की चादर बिछाई जा रही है, जिसके कारण भूमि में पानी के रिसाव पर पहरा लग गया है। प्रकृति के अत्यधिक दोहन से धरती का गर्भ सूखता ही जा रहा है।

बारिश से पहले पाल बांधने वाला समाज आज बांधों के भंवर में फंस गया है। यहीं कारण हैं कि सूखे को झेलने वाला राजस्थान का बाड़मेर बाढ़ के थपेड़ों को सहने को मजबूर है। बिहार को तारने वाले यह बांध अब उसको भी डुबाने लगे हैं। अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाली इन प्राकृतिक समस्याओं का इलाज है। पहले सामुदायिक जल प्रबंधन के तहत लोग बारिश की बूंदों को सहजने के लिए अपने घर की छत के जल को नीचे एक कुंड में साफ-सुथरे तरीके से एकत्र करते थे। बरसात का पानी खेत की फसल की जरूरत को पूरा करने के साथ अन्य क्षेत्रों के जल के साथ, पास के तालाब में इकट्ठा होता था। बाद में इस जल से खेती और घरेलू जल की जरूरतें पूरी की जाती थी।

रेगिस्तानी भूमि में करीब पांच छह फूट नीचे चूने की परत बरसाती पानी को रोके रहती थी। बाद में इसका उपयोग पीने व अन्य कामों के लिए किया जाता था। इस तरह सूखे की मार में यह पाल-ताल समाज को बचाकर रखते थे। अब हम इस तरह सामुदायिक जल प्रबंधन को भूलकर राज्य या भारत सरकार के बनाए बांधों की ओर देखने लगे हैं। ये बांध जहां नदियों को बांधकर उनकी हत्या करते हैं। वहीं, दूसरी ओर बाढ़ लाकर कहर बरसाते हैं।

बांध बनने से सामान्य वर्षों में जनता को लाभ मिलता है। लेकिन, बाढ़ आने पर पानी बांध को तोड़कर एकाएक फैलता है। कभी-कभी इसका प्रकोप इतना भयंकर होता है कि चंद घंटों में दस-बारह फुट तक पानी भी बढ़ जाता है और जनजीवन को तबाह करके रख देता



है। बांध बनने से सिल्ट फैलने की बजाए बांधों के बीच जमा हो जाती है। इससे बांध का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है। जब बांध टूटता है तो यह पानी वैसे ही तेजी से फैलता है जैसे मिट्टी का घड़ा फूटने पर बांधों से पानी के निकास के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। दो नदियों पर बनाए बांधों के बीच पचास से सौ किलोमीटर का एरिया कटोरानुमा हो जाता है। बांध टूटने पर पानी इस कटोरेनुमा क्षेत्र में एकट्ठा हो जाता है और इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इससे बाढ़ का प्रकोप शांत होने में काफी समय लगता है।

इन समस्याओं के चलते बांध बनने से परेशानियां बढ़ी हैं। जाहिर है कि बांध बनाने की वर्तमान पद्धति कारगर नहीं है। सामुदायिक जल प्रबंधन होने से पाल-ताल बनने बंद हो गए हैं, जिससे हमें हर साल बाढ़ विभीषिका से दो-चार होना पड़ रहा है।

अंधाधुंध बांध बनाने की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पहले विकल्प में नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह को बरकरार रखा जाना चाहिए। दूसरा विकल्प उंचे और स्थायी बांध बनाने की वर्तमान नीति का है। तीसरा विकल्प प्रकृतिप्रस्त बाढ़ के साथ जीने के लिए लोगों को सुविधा मुहैया कराने का है। इसमें फ्लड रूफिंग के लिए उंचे सुरक्षित स्थानों का निर्माण, सुरक्षित संचार एवं पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था शामिल है, जिससे बाढ़ के साथ जीवित रह सकें। धरती के ऊपर बड़े बांधों से अति गतिशील बाढ़ का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसे रोकने के लिए जल के अविरल प्रवाह को बनाए रखना होगा। इस काम से ही जल के सभी भंडारों को भरा रखा जा सकता है। चूंकि, बाढ़ और सूखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए इन दोनों के समाधान हेतु जल का सामुदायिक जल प्रबंधन ताल-पाल और झाल से ही संभव है।



## संसद के नए भवन के साथ इतिहास का निर्माण



अवधेश कुमार  
वरिष्ठ पत्रकार

संसद के नए भवन के उद्घाटन के समय लगभग राजनीतिक परिदृश्य वही था जो हमने इसके शिलान्यास- भूमि पूजन और योजना के संदर्भ में देखी। विपक्षी दलों के बड़े समूह ने इसका बहिष्कार किया। क्या करीब 100 वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा अपने शासन की मानसिकता से बनाया गया संसद भवन और उसके आसपास की पूरी रचना अनंतकाल तक रहनी चाहिए थी? आजादी के समय न हमारे पास इतना समय था और न संसाधन कि उसका परित्याग कर नए भवन में संविधान सभा चले या निर्वाचित सांसद संसदीय गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। कहा जा रहा है कि इसी भवन में हमारी आजादी की घोषणा हुई, संविधान सभा वहीं बैठी आदि आदि। क्या इसके आधार पर उसी संसद भवन को बनाए रखा जाएगा? इसमें लगातार फेरबदल और निर्माण होते भी रहे हैं। 1956

में और मंजिलें जोड़ी गई थी। 1975 में संसद एनेक्सी का निर्माण हुआ। 2002 में अपग्रेडेशन हुआ, पुस्तकालय भवन बना जिसमें कमेटी कक्ष के अलावा सम्मेलन कक्ष और एक सभागार तैयार करना पड़ा। यह भी कम पड़ा तो 2016 में संसद एनेक्सी का और विस्तार किया गया। संसद भवन परिसर की केवल मुख्य संरचना ही एक हद तक पुरानी है, शेष बहुत कुछ लगातार निर्मित हुआ है।

संसद भवन में अब वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रह गई थी। कई पीठासीन अधिकारियों ने संसद भवन के अंदर की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके समाधान करने की बात की। सन् 2026 में परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ने की संभावना है। नया संसद भवन सुविधाओं से युक्त हर तरह की आवश्यकता को पूरी करने वाली है। न केवल सांसदों की बढ़ी हुई संख्या अगले 100 वर्षों तक इसमें समायोजित हो सकेंगी बल्कि आधुनिक तकनीकों में भी अद्यतन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद अंग्रेजों का भवन ही हमारे लोकतंत्र की शीर्ष इकाई का स्थान हो यह समझ नहीं आता। अंग्रेजों ने संसद से लेकर आसपास के इलाकों को, जिसे सेंट्रल विस्टा



कहा जाता है, अपने अनुसार विकसित किया। उनमें पिछले 75 वर्षों में हुए परिवर्तन भी नाकाफी हैं। आवश्यक हो गया था कि कोई सरकार साहस कर भविष्य की चुनौतियों और आवश्यकताओं का आकलन करते हुए पूरे क्षेत्र का पुनर्निर्माण करे। विरोधी पार्टियां भले राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराए जाने को मुद्दा बनाएं, सच यही है कि वे पूरी परियोजना के विरुद्ध थे। न्यायालय से लेकर हर स्तर पर इसे बाधित करने की कोशिश हुई। राष्ट्रपति उद्घाटन करते इसमें समस्या नहीं थी पर प्रधानमंत्री करें इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना एक बात है, किंतु यह पूरे देश के लिए आत्मसंतोष का विषय होना चाहिए कि हम इस स्थिति में हैं कि विश्व के श्रेष्ठ संसद भवन निर्मित करा सकते हैं और उसके अनुरूप आसपास के सरकारी भवनों और स्थलों को भी उत्कृष्ट ढांचे में नए सिरे से खड़ा कर सकते हैं।

विरोध और समर्थन करने वाली पार्टियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। इस आधार पर मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा कि कितनी संख्या साथ है कितनी दूर। मुख्य बात यह है कि क्या विरोध करने वाली पार्टियों का देश, लोकतंत्र और उससे संबंधित ढांचे आदि को लेकर कोई विशेष विजन यानी कल्पना है या नहीं? नरेंद्र मोदी से सहमत हों, असहमत हों, एक विजन के तहत उन्होंने समस्त परिवर्तन किए हैं। 1967 से इंडिया गेट के पास मूर्ति की खाली जगह पर सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति लगी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाने के बाद किसी को शायद आज तक समझ नहीं आया कि वहां किसकी मूर्ति लगानी चाहिए। यह भी प्रश्न है कि 1947 के बाद 20 वर्षों तक वहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्यों थी? उसके साथ वहां युद्ध स्मारक बनाया गया। इंडिया गेट तक का राजपथ कर्तव्य पथ बना। तो इन सबके पीछे निश्चित रूप से देश के संदर्भ में यह सोच है कि इन स्थानों से क्या संदेश जाए और लोगों के अंदर कैसी मानसिकता पैदा हो।

सुभाषचंद्र बोस स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए लोगों के अंदर दासता से मुक्ति के लिए सैन्य-वीरत्व-आत्मोसर्ग भाव की प्रेरणा हैं। आधुनिक भारत में उनसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत कोई नहीं हो सकता। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में लालकिले से 22 अक्टूबर को तिरंगा फहराया जो, सुभाष बाबू द्वारा संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा का 75वां वार्षिक दिवस था। भारत के पास कभी अपना युद्ध स्मारक नहीं रहा जबकि हमें अनेक युद्ध लड़े, जिनमें हमारे जवानों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और अनेक वीरगति को प्राप्त हुए। इन सबको मिलाकर संसद और आसपास की सेंट्रल विस्टा परियोजना को देखना होगा। जीवन में स्थलों और प्रतीकों का व्यापक महत्व होता है क्योंकि वहां से आपकी मानसिकता बनती है और संदेश निकलता है। अनेक स्थलों का मोदी काल में इसी तरह या तो पुनर्निर्माण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है या उन स्थानों पर मूर्तियां लगी हैं।

वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिवस

पर संसद भवन के उद्घाटन से भी निःसंदेह विपक्ष को समस्या हो सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में इसे राष्ट्र निर्माताओं का अपमान तक बता दिया है। मोदी एकाएक वीर सावरकर तक नहीं पहुंचे हैं। वे महात्मा गांधी से आरंभ करते हुए सरदार बल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों को महत्व देते यहां तक आए हैं। संत रामानुजम से लेकर आदि शंकराचार्य की मूर्तियों का भी उन्होंने अनावरण किया है। तो यह देश के तस्वीर की दृष्टि है जिसमें व्यापकता है। भारत यदि विश्व के प्रमुख देशों की कतार में खड़ा है तो उसके अनुसार उसके सरकारी भवनों में भी भव्यता होनी चाहिए। दिल्ली आने वाले या रहने वाले लोगों को संसद के आसपास पूरे सेंट्रल विस्टा में निर्मित या निर्माणाधीन स्थलों को देखकर भव्यता का अहसास होता है। आज भारत जैसे देश के लिए स्वयं को हर स्तर पर एक बड़े ब्रांड के रूप में पेश करने पर किया गया यह खर्च किसी दृष्टि से अनावश्यक नहीं कहा जाएगा। यह दृष्टि का ही अभाव था कि 14 अगस्त, 1947 को प्राप्त सेंट्रल यानी राजदंड को पंडित नेहरू ने वह स्थान नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। इसे 1960 से पहले आनंद भवन और 1978 से इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। जब भारत के सत्ता हस्तांतरण में तमिल विद्वान पंडितों के मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्राप्त किया तो उसे संसद भवन के केंद्र में होना चाहिए था। भारतीय संस्कृति में इनका केवल प्रतीकात्मक नहीं सूक्ष्म प्रभावकारी महत्व है। देश में किसे याद था कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समय भारतीय परंपरा के अनुसार राजदंड स्वयं नेहरू जी ने ग्रहण किया जिसे बाद में शायद विचारधारा के अनुकूल न मानते हुए दिल्ली से बाहर भेज दिया गया। क्या राजदंड आनंद भवन और संग्रहालय के लिए दिया गया था? मोदी सरकार नहीं होती तो उस राजदंड को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम तो छोड़िए कल्पना भी कोई नहीं करता।

स्पष्ट है कि विरोधी इस महत्वपूर्ण अवसर का महत्व नहीं समझ पाये। वे यह भी नहीं सोच पाये कि बरसों बाद जब संसद के उद्घाटन की तस्वीरें देखी जाएंगी या फिर कौन-कौन शामिल थे इसका उल्लेख होगा तो उनमें इस समय के बहिष्कार करने वाले विपक्षी नेता और सांसद नहीं दिखेंगे। इतिहास के अध्याय से स्वयं को वंचित रख ये नेता क्या पाना चाहते हैं? कार्यक्रम में शामिल होकर भी आगे अपना विरोध कायम रख सकते थे। इतिहास किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो अध्याय लिखे जाने हैं वे लिखे जाते हैं और नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा और सिंगोल के साथ स्वतंत्र भारत में इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया है।



# इतिहास में गुम चोल एवं अन्य भारतीय राजवंश



प्रणव कुमार  
शिक्षाविद एवं वरिष्ठ स्तंभकार

संसद के नए भवन में राजधर्म और न्याय के साथ-साथ सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल की स्थापना ने गौरवशाली चोल राजवंश की याद दिलाने का भी काम किया है।

कम-से-कम स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में विषयवस्तु का चयन एवं निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए था कि वर्तमान को अतीत के गौरवशाली अध्यायों का समग्र एवं संपूर्ण बोध हो ताकि भविष्य की मजबूत आधारशिला रखी जा सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतिहास के पाठ्यक्रमों का चयन एवं निर्धारण कुछ इस प्रकार किया गया है कि जहाँ मुगलों की पूरी-की-पूरी वंशावली एवं ब्रितानी लॉर्डों-राजाओं की क्रमबद्ध सूची याद रह जाती है, वहीं लंबे समय तक यशस्वी एवं प्रभावी शासन करने वाले चोल या अन्य भारतीय राजवंशों के दो-चार राजाओं के नाम भी सहसा याद नहीं आते। आज कितने ऐसे विद्यार्थी, शिक्षक, आम या प्रबुद्ध भारतीय होंगे, जिन्हें चोल राजवंश के राजाओं के नाम, उनके काम, उनके राज्य-विस्तार, कला, स्थापत्य, साहित्य एवं संस्कृति आदि क्षेत्रों में उनके योगदान इत्यादि के बारे में समुचित एवं सम्यक जानकारी होगी? शायद बहुत कम या बिलकुल नगण्य।

उल्लेखनीय है कि आज से लगभग 2300 वर्ष पहले 300 ईसा पूर्व में चोल राजवंश की स्थापना हुई थी, जिसका प्रभाव 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। अशोक के शिलालेख, पाणिनी की अष्टाध्यायी, कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक, संगम साहित्य (100-250 ई.), शैव संतों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, बौद्धग्रंथ महावंश, संस्कृत, तमिल, तेलगू एवं कन्नड़ भाषा के अनेक अभिलेखों, उस दौर के सिक्कों तथा विदेशी विवरणों जैसे अनेक स्रोतों से चोलों के गौरवशाली इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। नवीं सदी के मध्य से विजयालय के शासनकाल (848-871 ई.) में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। विजयालय की वंश-परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर लगभग साढ़े चार सौ (848-1279 ई.) से भी अधिक वर्षों तक शासन किया। इनमें आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुल्लोतुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुल्लोतुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुल्लोतुंग तृतीय, राजराज तृतीय एवं राजेंद्र चोल तृतीय आदि प्रमुख थे। राजराज प्रथम (985-1014 ई.) एवं राजेंद्र प्रथम (1014-1044 ई.) चोल राजवंश के सबसे प्रतापी एवं पराक्रमी



राजा थे। इनके शासन-काल में चोल साम्राज्य का प्रभाव एवं विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु से लेकर वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया आदि तक फैला हुआ था। उनकी नौसेना में 1000 युद्धपोत और 10 लाख से अधिक सैनिक थे। उनकी नौसेना में महिलाएँ भी थीं। उन्होंने बंगाल की खाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसलिए उसका प्राचीन नाम 'चोल झील' भी है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इतनी विकसित एवं उन्नत नौसेना चोलों की सामरिक दूरदर्शिता एवं शक्ति की परिचायक है।

चोलों के विभिन्न अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इनका शासन-तंत्र सुव्यवस्थित था। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था जो मंत्रियों एवं राज्याधिकारियों की सलाह से शासन करता था। उनकी नौकरशाही सुसंगठित थी, जिसमें अधिकारियों के उच्च (पेरुंदनम्) और निम्न (शिरुदनम्) दो वर्ग थे। केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए 'कणकाणि' नाम के अधिकारी होते थे। सुशासन की दृष्टि से संपूर्ण राज्य को अनेक मंडलों में विभाजित किया गया था। मंडल को भी कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम, ग्रामम जैसी छोटी इकाइयों में बाँटा गया था। संपूर्ण भूमि नापी हुई थी और करदायी तथा करमुक्त भूमि में बँटी थी। नगरम् उन स्थानों की सभाएँ थीं, जहाँ व्यापारी वर्ग प्रमुख था। ग्रामसभाओं को 'उर' या 'सभा' कहा जाता था। इन 'सभाओं' की कार्यकारिणी परिषद (आडुगणम्) का चुनाव जनसामान्य में से योग्यता के आधार पर निश्चित अवधि के लिए किया जाता था। उत्तरमेरूर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार ग्राम-शासन 'सभा' की पाँच उपसमितियों द्वारा किया जाता था। 'सभाएँ' शासन के लिए स्वतंत्र थीं तथा उनके कामकाज में राजा का भी हस्तक्षेप नहीं के बराबर था। 'सभाओं' के कार्यों के संचालन के लिए अत्यंत कुशल और संविधान के नियमों की दृष्टि से संगठित और विकसित समितियों की व्यवस्था थी, जिन्हें



‘वारियम्’ कहते थे। न्याय के लिए गाँव और जाति की सभाओं के अतिरिक्त राज्य द्वारा स्थापित न्यायालय भी थे। निर्णय सामाजिक व्यवस्थाओं, लेखपत्र और साक्षी के प्रमाण के आधार पर होते थे। सुसंगठित नौकरशाही के साथ उच्च कोटि की कुशलतावली स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का सुंदर और सफल सामंजस्य चोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय जीवन के विभिन्न अंगों के लिए विविध सामूहिक संस्थाएँ थीं जो परस्पर सहयोग से कार्य करती थीं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि चोलों की शासन-व्यवस्था में आज की लोकतांत्रिक एवं स्थानीय स्वायत्तशासी शासन-व्यवस्था की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है।

दक्षिण के कुछ सिने सितारों ने पूर्वाग्रह या कथित पंथनिरपेक्षतावादी मानसिकता के कारण भले कहा हो कि चोल हिंदू राजा नहीं थे, पर सत्य यह है कि अधिकांश चोल शासक भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। वे भी अन्य हिंदू राजाओं की भाँति उदार, सहिष्णु एवं प्रजा-वत्सल थे। उनके राज्य में जैन, बौद्ध, पारसी एवं ईसाई मतावलंबियों को भी समान अधिकार प्राप्त थे। उनके द्वारा बनवाए गए बृहदेश्वर-राजराजेश्वर, गंगईकॉड चोलपुरम, ऐरावतेश्वर आदि मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में, जबकि दरासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर और गांगेयकॉड चोलपुरम के मंदिर को 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में सम्मिलित किया गया। इनमें तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केन्द्रीय गुम्बद से लोगों को अत्यधिक आकर्षित करता है। इसके तेरह मंजिलें भवन की ऊँचाई लगभग 66 मीटर है। मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है।

यह कला की प्रत्येक शाखा - वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, प्रतिमा विज्ञान, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्णकला का भंडार है। यह मंदिर उत्कीर्ण संस्कृत व तमिल पुरालेख एवं सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह भी है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। शिखर पर स्वर्णकलश स्थित है। जिस पाषाण पर यह कलश स्थित है, अनुमानतः उसका भार 2200 मन (88 टन) है और यह एक ही पाषाण से बना हुआ है। मंदिर में स्थापित विशाल, भव्य शिवलिंग को देखने पर उनका बृहदेश्वर नाम सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। मंदिर में प्रवेश करने पर गोपुरम् के भीतर एक चौकोर मंडप है। वहाँ चबूतरे पर नन्दी जी विराजमान हैं। नन्दी जी की यह प्रतिमा 6 मीटर लंबी, 2.6 मीटर चौड़ी तथा 3.7 मीटर ऊँची है। भारतवर्ष में एक ही पत्थर से निर्मित नन्दी जी की यह दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। ऐरावतेश्वर मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। शिव को यहाँ ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की

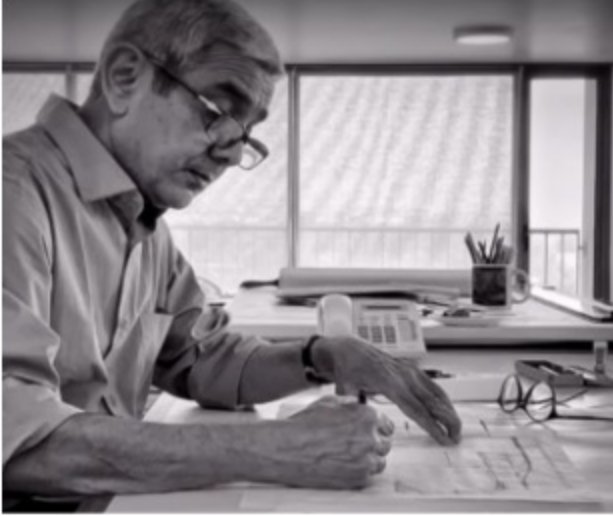
पूजा की गई थी। यह मंदिर भी कला एवं स्थापत्य कला का भंडार है और इसमें पत्थरों पर शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। गंगैकोण्ड चोलपुरम् तमिलनाडु के अरियालुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1035 ईस्वी में राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा कराया गया था। देश के उत्तरी भाग में गंगा को जीतने के बाद, उन्होंने गंगा के विजेता के रूप में गंगईकॉड चोल नाम का अधिग्रहण किया था। इस मंदिर में असाधारण गुणवत्ता की मूर्तियाँ हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग एक ही चट्टान से बनाया गया है। चोल कांस्य प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। भोगशक्ति और सुब्रह्मण्य के कांस्य चोल धातु के प्रतीक की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति उनकी मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के दूसरे कई रूप, ब्रह्मा, सप्तमातृका, लक्ष्मी तथा भूदेवी के साथ भगवान विष्णु, अपने अनुचरों के साथ श्रीराम और सीता, शैव संत और कालियदमन करते हुए श्रीकृष्ण की मूर्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं।

सिंचाई के लिए चोल नरेशों ने अनेक कुएँ एवं तालाब खुदवाए तथा नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बाँध से घिरे जलाशय (डैम) बनवाए। करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बाँध बनवाया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकॉड-चोलपुरम् के समीप एक झील खुदवाई, जिसका बाँध 16 मील लंबा था। इसको दो नदियों के जल से भरने की व्यवस्था की गई थी और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए पत्थर की प्रणालियाँ और नहरें आदि बनवाई गईं। आवागमन की सुविधा के लिए प्रशस्त राजपथ और नदियों पर घाट भी निर्मित हुए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शासन-तंत्र से लेकर कला, वास्तु, स्थापत्य, साहित्य, संस्कृति, भवन एवं सड़क निर्माण आदि क्षेत्रों में चोल राजाओं का अभूतपूर्व योगदान था।

परंतु चोल एवं अन्य भारतीय राजवंशों के बृहत एवं विस्तृत योगदान पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकें लगभग मौन हैं। दुखद है कि हमारे विद्यालयों-विश्वविद्यालयों में केवल दिल्ली केंद्रित इतिहास को पढ़ने-पढ़ाने या विदेशी आक्रांताओं के गौरव-गायन पर जोर दिया जाता है। समग्र, संपूर्ण एवं संतुलित भारतबोध के लिए आज इस बात की महती एवं अविलंब आवश्यकता है कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों व पाठ्यक्रमों में आमूल-चूल परिवर्तन हो और उनमें अतीत के तमाम गौरवशाली अध्यायों, मसलन - चोल, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, पल्लव, परमार, मैत्रक, राष्ट्रकूट, वाकाटक, काकोट, कलिंग, काकतीय, सातवाहन, विजयनगर, ओडेयर, अहोम, नगा, सिख आदि तमाम प्रभावशाली राज्यों एवं राजवंशों को सम्मिलित कर - शासन के उनके तौर-तरीकों, अन्य राज्यों एवं देशों से उनके संबंधों, आयात-निर्यात की साझेदारियों, व्यापारिक नीतियों एवं स्थितियों, वाणिज्यिक मार्गों, सैन्य-संरचनाओं, सामरिक रणनीतियों, विजय-यात्राओं तथा कला, धर्म, समाज, साहित्य व संस्कृति आदि के प्रति उनके योगदान एवं दृष्टिकोण को विस्तारपूर्वक पढ़ा-पढ़ाया जाए।



# संसद के नए भवन के शिल्पकार पद्म श्री बिमल पटेल के साक्षात्कार के कुछ अंश



**संसद के नए भवन का निर्माण करना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी?**

संसद का नया भवन इस प्रकार बनाना था कि यहां की विरासत को भी हानि ना पहुंचे और साथ-साथ एक ऐसा भवन भी बने जिसमें भारत की विरासत के दर्शन हों। हमारे राष्ट्र की ऐसी झलक दिखे जो हमारी संप्रभुता और अखंडता को परिलक्षित करे। इसे बनाना एक आनंद भी था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी क्योंकि इससे सभी भारतीयों की आशाएं और प्रधानमंत्री जी का विजन जुड़ा हुआ था। मेरे साथ मेरी कुशल टीम, कॉन्ट्रेक्टर, सी.पी.डब्ल्यू.डी और अन्य कई लोगों ने मिल कर कार्य किया।

**संसद का नया भवन त्रिभुजाकार है। यह आकार देने के पीछे क्या कारण था?**

पहले हमने पुरानी बिल्डिंग को स्टडी किया। पुरानी बिल्डिंग संसद भवन कभी नहीं थी, वह एक काउंसिल हाउस था जिसे हमने संसद के रूप में अपना लिया था। काउंसिल हाउस में जो चेंबर था वह अब लोकसभा है, जिसे 150 लोगों के बैठने के लिए बनाया गया था लेकिन आज उसमें 542 लोग बैठते हैं। हमें अध्ययन में पता चला कि आवश्यकताओं को देखते हुए हमें नया भवन तो बनाना होगा। हमने नया भवन पास में ही बनाने का निर्णय लिया जिससे आगे चलकर दोनों भवन मिलकर एक कॉमन कॉम्प्लेक्स बन जाएं। हम यह भी चाहते थे कि दोनों भवन में कुछ मेल हो लेकिन फिर भी हम इसे पुराने संसद की नकल करके नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि यह भारत का अपना संसद भवन बनने वाला था जो अपने आप में विशिष्ट हो। इसीलिए हमने बाहर का

पत्थर और भवन की ऊंचाई पुराने भवन जैसी ही रखी है। दोनों एक जैसे होकर भी भिन्न हैं।

यह प्लॉट त्रिभुजाकार था और अपेक्षाएं अधिक थी। यह इस प्रकार के भवन के लिए एक अच्छा आकार था। हमने निर्धारित किया कि एक कोने में राज्यसभा, एक में लोकसभा और तीसरे कोने में सेंट्रल लाउन्ज बनाएंगे जो लोगों के मिलने जुलने के लिए एक उचित स्थान होगा।

**क्या पुरानी कार्यकारी संसद के इतने नजदीक नए भवन का निर्माण कार्य करना चुनौतीपूर्ण रहा?**

इस भवन का निर्माण ढाई साल में हुआ, 6-7 महीने में हमने डिजाइनिंग की। इस बीच बहुत सी चुनौतियां सामने आईं। एक ओर पुराने भवन में संसद की कार्यवाही नियमित चल रही थी, इतने नजदीक हम नए भवन का निर्माण कर रहे थे और उस समय कोरोना काल भी था। कोरोना के समय लॉकडाउन में हम सब ऑनलाइन काम कर रहे थे। कोरोना के दौरान भी काम चलता रहा क्योंकि हमारा लक्ष्य स्पष्ट था। प्रधानमंत्री जी ने हमें जल्द से जल्द इस निर्माण को पूर्ण करने का टारगेट दिया था। एक धारणा यह भी है कि भारत में भवन बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। हमें यह प्रयोग भी करके दिखाना था कि हमारे यहां भी कम समय में भव्य भवन का निर्माण हो सकता है। यदि सब मिशन मोड में साथ मिलकर कार्य करें तो ऐसी विषम चुनौतियों से भी निपटा जा सकता है।

**आपकी टीम में कितने लोग थे?**

मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। जब हम फुल डिजाइन का काम कर रहे थे तो मेरी कंपनी एच.सी.पी. (H.C.P.) थी और इसके साथ ही कई स्पेशलिस्ट कन्सल्टेंट थे। हमारे साथ स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, अकॉस्टिक्स, मैकेनिकल, फर्नीचर, ऐसी लगभग 41 अलग-अलग फर्म थीं जिन्होंने इस डिजाइन में कुछ ना कुछ योगदान दिया। हमारा काम था इन सभी डिजाइंस को इंटीग्रेट करना। जब हम साथ में काम कर रहे थे तब एक बार मैंने गिनती की तो पाया कि हम 450 लोग डिजाइन पर काम कर रहे थे। यह एक भरसक प्रयास था। इन्टीरियर, फर्नीचर, अकॉस्टिक्स, फेब्रिक, प्लंबिंग, एयर कन्डिशनिंग सभी चीजों को मिला कर डिजाइन बनता है। सभी ने मिल कर काम किया। सी.पी.डब्ल्यू.डी ने ही हमें नियुक्त किया था, उनके इंजीनियर भी हमसे जुड़े हुए थे जो इस गिनती में आए ही नहीं, और इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रेक्टर!



आपने संसद के नए भवन को डिजाइन किया है, इसकी ऐसी कौन सी जगह है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है? जो मात्र मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में ही नजर आएगी।

इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं। इतना बड़ा चेंबर, आपको ज्यादा डेमोक्रेटिक (लोकतान्त्रिक) फंक्शनिंग संसद में इतना बड़ा चेंबर नहीं मिलेगा। कई बार बहुत बड़े चेंबर होते हैं पर वे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग वाले नहीं होते। हमने भारत के विभिन्न हिस्सों की वास्तुशिल्प कला का उपयोग किया है जिससे यह भारत की विविधता को प्रतिबिंबित करे। संसद के नए भवन का प्रांगण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पूरे आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर डेकोरेशन में भारतीय चिन्हों को उकेरा गया है। प्रांगण की मुख्य थीम है राष्ट्रीय पेड़। यहां बीच में बरगद का पेड़ है। सभी ओर बनी प्रत्येक जाली अलग है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से पेड़ों की आकृतियों से प्रेरणा लेकर इन जालियों को बनाया गया है। संसद का नया भवन विशेष इसीलिए भी है क्योंकि यह हमारा है, भारतीय है। यहां एकता और विविधता को दर्शाते विशेष चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे।

#### क्या यह भवन पर्यावरण संतुलन की ओर एक कदम है?

यह पूरी तरह से एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है। संसद के नए भवन में ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा गया है। यहां वृक्षों को काटा नहीं गया अपितु उनका स्थानांतरण किया गया है। भवन का निर्माण शुरू होने से पहले ही प्लानिंग टीम ने तय किया था कि यहां पर मौजूद जितने वृक्ष हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। हमारा उद्देश्य था कि जो भी सिस्टम लगे हैं वह कम से कम ऊर्जा में अधिकतम कार्य करने में सक्षम हों। कुछ पुराने पेड़ इसी भवन में रखे गए हैं। पेड़ों को रखने के लिए प्रांगण के डिजाइन में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया।

#### लोकसभा को मोर और राज्यसभा को कमल की थीम पर ही क्यों तैयार किया गया ?

जब इसकी चर्चा सांसद और अन्य लोगों से की तो सभी का यह भाव था कि इसका डिजाइन पुराने संसद भवन के डिजाइन से मेल खाता हुआ होना चाहिए। पुरानी संसद में लोकसभा में हरा और राज्यसभा में लाल रंग है। एक संस्था के रूप में संसद भारत की विविधता को जोड़कर एक राष्ट्र बनाती है इसीलिए हमें राष्ट्रीय चिन्ह भी प्रयोग में लेने थे।

हमने विचार किया कि इसका क्या थीम रखें जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह भी हो और हरा भी, तो अपने आप ही निकल कर



आया कि मोर राष्ट्रीय पक्षी भी है और हरा भी। इसी प्रकार राज्यसभा के लिए कमल की थीम रखी गई। मोर की थीम रखने से जब रंग और राष्ट्रीय चिन्ह दोनों बातें पूर्ण हो गईं तो हम आश्वस्त थे कि थीम निर्धारित करने के लिए यह एक उचित तरीका है फिर फेब्रिक, फर्नीचर, जाली, वुड पैनलिंग में भी मोर और कमल की थीम लेकर हमने डिजाइन किया।

#### क्या संसद का नया भवन में राष्ट्रीयता के भाव से भरपूर है?

संसद में 3 त्रिभुज है। एक कोने में लोकसभा है जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दूसरे कोने में राज्यसभा है जहां राष्ट्रीय फूल कमल है। तीसरे कोने में सेंट्रल लाउन्ज है जहां प्रांगण के बीच में राष्ट्रीय पेड़ बरगद है और शिखर पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। सार्वजनिक प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' भी लिखा है। इस भवन के निर्माण और साज-सज्जा में कई राष्ट्रीय प्रतीकों को रखा गया है। हमें एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना था जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अनुभूति हो कि यह उनका अपना भवन है।

#### आज यह भवन आपके सामने है। लोकतंत्र के इस भव्य मंदिर को देखकर आपको कैसी अनुभूति होती है ?

आनंद तो बहुत है लेकिन कठिनाईयां भी बहुत थी। बहुत लोगों ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। हजारों लोगों ने साथ मिलकर काम किया। मुझे जितने भी पुरस्कार मिले हैं उनमें संसद के नए भवन का निर्माण मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।

आभार... संसद टी.वी.



# भारत को निहारता विश्व समुदाय



डॉ. अनिल कुमार निगम  
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं  
जनसंचार संकाय, आईएमएस गाजियाबाद

पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूना, वैश्विक महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का मोदी से कहना कि मुझे आपका आटोग्राफ लेना चाहिए और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज का मोदी को बॉस कहकर पुकारना हाल ही की चंद बड़ी घटनाएं हैं। ये घटनाएं संकेत देती हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का प्रभाव पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि वैश्विक समुदाय अनेक जटिल और गूढ़ मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी के लिए भारत की ओर निहार रहा है।

यही नहीं, जी 20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत की स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ है। सर्वप्रथम, चर्चा करते हैं पापुआ न्यू गिनी की जहां मई महीने में भारत के प्रधानमंत्री जी-7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हुए थे। वहां उनका न केवल जोरदार स्वागत हुआ बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मेजबान देश पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। यहां जैसे ही मोदी अपने विमान से उतरे, मारापे ने उनके पैर छुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारापे की पीठ थपथपाते हुए उन्हें उठा लिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (आईसीसीआर) के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने इस पर लिखा, “वैश्विक समुदाय इस तरह से भारत, भारत के नेता और संस्कृति का सम्मान करता है।” महिला पहलवान बबीता फोगाट ने भी इस पल को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा, ‘कोरोना महामारी में वैक्सीन भेजकर पीएम मोदी ने वहां के लोगों के लिए किसी फरिश्ते जैसा काम किया था। आज वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत को दुनिया मान रही है।’

दूसरा प्रसंग है 20 मई को आयोजित होने वाली जापान में क्वाड बैठक का। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनियाभर में बढ़ रही है। मोदी के मुरीद होने वालों में विश्व के कई बड़े नेता शामिल हैं। कथित तौर पर वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांग लिया। बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन और आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने मोदी से एक रोचक बात का जिक्र किया। बाइडेन ने मोदी को बताया कि अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं जिसके लिए



उनके पास कई आवेदन आ रहे हैं। बाइडेन ने कहा, ‘मुझे आपके कार्यक्रमों के लिए लोगों से लगातार अनुरोध मिल रहे हैं जो मेरे लिए चुनौती बन गया है। वहीं, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी ने मोदी की लोकप्रियता की तारीफ करते हुए कहा कि सिडनी में 20 हजार की क्षमता वाला कम्युनिटी रिसेशन है लेकिन फिर भी वह लोगों के सभी अनुरोधों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

तीसरा प्रसंग है आस्ट्रेलिया के विदेश यात्रा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने ‘द बॉस’ कहकर पुकारा। हालांकि यह उनके आधिकारिक भाषण का हिस्सा नहीं था। कार्यक्रम के बाद अल्बानीज ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह बताया था कि मोदी को बॉस बोलना उनके मन की बात थी।

वास्तविकता तो यह है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब भारत को वैश्विक समुदाय ने सराहा हो। ध्यातव्य है कि कोविड महामारी के समय भारत की हाथ जोड़ कर नमस्कार करने की परंपरा को संपूर्ण विश्व ने सराहा और उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। दरअसल, हाथ जोड़कर नमस्ते करने की परंपरा एक संक्रमण रहित शैली है। इसलिए इसने सभी को अपनी ओर तेजी से आकर्षित किया। इसके अलावा कोविड महामारी से निजात पाने के लिए विकसित किए गए कोविड वैक्सीन की लाखों डोज भारत ने विश्व के अनेक देशों को जिस तरीके से बढ़चढ़ कर मुहैया कराई थीं, उसकी न केवल उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई बल्कि इसका सकारात्मक असर विश्व के सभी देशों पर पड़ा। भारत की यह मानवीय उदारता विश्व के अनेक देशों के मन मस्तिष्क के पटल पर स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों के पश्चात ही 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। उसके पश्चात वर्ष 2015 से पूरे विश्व में 21 जून को हर वर्ष विश्व योग दिवस के नाम से मनाया जाता है।



विश्व में सर्वाधिक मजबूत संगठन के रूप में उभरे समूह जी-20 की अध्यक्षता करने के कारण भारत आज अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा पूरा विश्व को मनवा रहा है। डिजिटल क्रांति में अग्रणी होने के साथ-साथ पिछले नौ वर्षों में भारत विश्व पटल पर एक सशक्त ताकत बन कर उभरा है। यही कारण है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पूरा विश्व यूक्रेन-रूस युद्ध के समाधान के लिए भारत की तरफ आस लगाए बैठा है।

भारत इस वर्ष जी 20 की अध्यक्षता कर रहा और अगले वर्ष क्वाड की अध्यक्षता करने वाला है। जी-20 में अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ

आदि देश सम्मिलित हैं।

जी-20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत ने न केवल एक सुव्यवस्थित और उपयोगी शिखर सम्मेलन सुनिश्चित करने का जिम्मा उठाया है, बल्कि वह इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखने का एक नया तरीका स्थापित करने के अवसर के रूप में भी उपयोग कर रहा है। यही नहीं, वह जी-20 के माध्यम से अपने आधारभूत ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना रहा है। भारत अब विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। भारतीय अवधारणा-‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की बात अब हर प्लेटफार्म पर होने लगी है। अतः कहा जा सकता है कि आज भारत विश्व गुरु बनने के संकल्प की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है।

## अपराजिता

# आत्मनिर्भरता की कहानी



बागेश्वर के कपकोट की बसंती कपकोटी बड़ा रही महिलाओं के हथ्यों की ताकत

आत्मनिर्भर महिलाएं पथप्रदर्शक हैं जो सभी बाधाओं को तोड़ती हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनके अन्दर दृढ़संकल्प, दृढ़ता और स्वयं के लिए मजबूत भावना एक रोल मॉडल की तरह कार्य करता है जिससे समाज प्रगतिशील होता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के पीछे का कारण कहीं न कहीं वहां का सामाजिक ताना-बाना होता है। जो आर्थिक सम्पन्नता का आधार होता है। आइये बात करते हैं ऐसे ही उत्तराखण्ड के बागेश्वर जिले की महिलाओं की। जिनका तटस्थ संकल्प न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बना रहा बल्कि युवाओं को पलायन करने से रोक भी रहा है। ये अपनी घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी से लेकर खेती-बाड़ी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं साथ अतिथि देवो की सनातन परंपरा को आत्मसात करते हुए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही हैं। बागेश्वर के लीती गांव की 30 महिलाओं ने होमस्टे को अपनी जीविका का साधन बना लिया। इससे होने वाली आमदनी से युवा आकर्षित हुए बिना न रह सके। बागेश्वर जिले में लगभग 114 होमस्टे संचालित है जिसमें अकेले 30 लीती गांव में ही हैं। कोरोना काल में दिल्ली-एनसीआर में कार्य करने वाले लोगों ने यहां आकर खुद को आइसोलेट किया एवं वहीं से रहकर काम किया। जिससे होमस्टे चलाने वाली महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी हुयी। लीती में होमस्टे चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में वर्ष 2018 से आपसी सामंजस्य से होमस्टे चलाया जा रहा है। छः महिलाओं ने अपनी जमा पूंजी लगाकर इस कार्य को बढ़ाया और अब संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।

जब महिला आत्मनिर्भर होती है तो वह शिक्षा एवं आजीवन सीखने के महत्व को भी समझती है। वह अपने निजी व व्यवसायिक विकास को प्राथमिकता देती है और अपने जैसी अन्य महिलाओं को प्रेरित करती है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने वाले कौशल सवारंती है जिससे उसे विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल बनाकर रखें और उचित अवसरों से लाभान्वित होने में सहायक बनें। आइये बात करते हैं ऐसी ही बागेश्वर की बसंती कपकोटी की जिनका नारी सशक्तीकरण में विशेष योगदान है। 1998 से लगातार अपने क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाकर बालबाड़ी के माध्यम से कपकोट के सुदूरवर्ती गांव तारसाल, चौड़ा, वाछम, बनार, गोगिना, कर्मी आदि गांवों में छ आरोग्य मंदिर बनवाएं। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं अधिकारों के लिए जागरूक किया। साथ ही 2019-20 में महिला मंच प्रधानों के नेतृत्व का बीड़ा उठाया। कपकोटी में 28, गरुड़ में 39 और बागेश्वर विकास खंड में 10 ग्राम पंचायतों का महिलाओं का समूह उनसे जुड़ा हुआ है।

वहीं शामा और कपकोट की 49 महिलाओं को उद्यमिता विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया जहां उन्हें रिंगाल से टोकरी, पूजा थाल, डलिया, फूलदान बनाने का कौशल सिखाया गया। शिविर के समापन में सीखे कौशल के आधार पर परीक्षण किया गया और महिलाओं ने बहुत ही आकर्षक उत्पाद बनाये। साथ ही शिविर में महिला समूह की 25 सदस्यों ने अचार, जूस और पनीर बनाने का प्रशिक्षण लिया। मास्टर ट्रेनर शामा ग्रोथ सेंटर के अध्यक्ष राजेन्द्र कोरंगा ने महिलाओं को विभिन्न फलों के उत्पादन करने के लिए भी प्रेरित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि संसाधन उपलब्ध कराकर महिलाओं को यदि उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वयं भी सशक्त होगी और अर्थव्यवस्था को गति भी प्रदान करेगी। इसी को चरितार्थ किया है बागेश्वर की नारीशक्ति ने।

निश्चित रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं अपनी स्वायत्तता को महत्व देती हैं और उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होता है तभी तो वह उचित निर्णय लेती हैं। अपने मूल्यों व लक्ष्यों को संरक्षित कर अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप चुनाव करने का साहस उनमें कूट-कूट कर विद्यमान रहता है।



# भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति (रूस-यूक्रेन)



डॉ. प्रीता पंवार  
सेवानिवृत्त प्राचार्या, लेखिका एवं संपादक  
(फरीदाबाद)

भारत आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के ऐसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसे एक-एक कदम फूँक कर रखने की आवश्यकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे घातक देश भारत को पड़ोसी के रूप में विरासत में मिले हैं। एक ओर यदि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है तो दूसरी ओर चीन भारत में गाढ़े बगाहे घुसपैठ कर भारतीय सीमा में अतिक्रमण करता रहा है। दोनों ही देश भारत की सुरक्षा के लिए निरंतर रूप से खतरा बने हुए हैं। यही कारण है कि भारत को अपनी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल अपनी सैन्य शक्ति अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संबंधों व प्रयासों को भी चाक-चौबंद रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियाँ वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली होकर उभरी-अमेरिका और रूस। दुनिया के अधिकांश देश दो खेमों में बँट गए किंतु स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और सभी देशों के साथ समानता, मैत्री और भाईचारे के आधार पर संबंध बनाने को वरीयता दी। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली। भारत चीन मैत्री के नारे लगे, चीन के साथ परस्पर सह अस्तित्व के आधार पर संबंध बने किंतु इन सबकी अंतति भारत चीन युद्ध में हुई। भारत की शर्मनाक हार हुई। चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। भारत न केवल अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने को बाध्य हुआ बल्कि अपने कूटनीतिक प्रयासों पर पुनर्विचार करने पर भी बाध्य हुआ।

उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। अमेरिका लगातार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था। चीन की भारत पर कुदृष्टि तो थी ही। भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति पर कायम रहना राष्ट्र के लिए घातक हो गया था। राष्ट्र हितों की रक्षा करते हुए भारत ने रूस के साथ संधि की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कूटनीतिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 1971 में पुनः

पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि भारत ने पाकिस्तान के साथ दोनों युद्ध जीते किंतु भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में कोई कमी न आई। भारत के रूस के साथ सामरिक व कूटनीतिक संबंध प्रगाढ़ होते चले गए।

वैश्विक समीकरण भी बदलते चले गए। नब्बे के दशक में सोवियत यूनियन टूट कर बिखर गया और पूर्वी यूरोप व उसके आसपास कई छोटे-छोटे देश उभर आए और उनमें से एक है यूक्रेन! रूस बेशक टूटा किंतु सामरिक दृष्टि से मजबूत रहा और भारत का स्थाई समर्थक व हथियार देने वाला एक विश्वसनीय मित्र भी। रूस से अलग हुए छोटे छोटे देशों पर पश्चिमी देश, विशेषकर नाटो देश अपना प्रभाव जमाने लगे और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बदलने लगा। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के लिए नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। इस युद्ध में चीन पूरी तरह से रूस के साथ है और संभवतः वो अपना यह प्रभाव रूस के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करने में कर सकता है। चीन रूस का पड़ोसी राष्ट्र है और चीन के भी रूस के साथ सीमा संबंधी विवाद रहे हैं। चीन एक आक्रामक देश के रूप में कुख्यात है और रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि इस समूचे क्षेत्र में चीन अपना दबदबा बनाए। अतः एक विशेष सीमा तक ही रूस चीन पर विश्वास कर सकता है। भारत कभी भी रूस के साथ अपने संबंधों को हलके स्तर पर नहीं ले सकता क्योंकि समय साक्षी है कि रूस सदैव भारत के साथ खड़ा रहा है - चाहे वो भारत पाक युद्ध हो, परमाणु परीक्षण हो या कश्मीर का मसला हो। वास्तव में रूस भारत का इतना बड़ा रणनीतिक सहयोगी है कि उसने भारत चीन सीमा विवाद तक में अपनी निष्पक्षता बरकरार रखी।



लेकिन ऐसे में उनका क्या किया जाए जो भारत में यूक्रेन के समर्थन में खड़े होकर सड़कों पर नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इन तमाम लोगों को या तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ नहीं है या वो भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से अवगत नहीं हैं। दरअसल ऐसे सभी भारतीय जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें सदैव यह बात याद रखनी चाहिए कि यूक्रेन का हमेशा से ही भारत विरोधी रुख रहा है। यूक्रेन ने परमाणु परीक्षण मुद्दे पर कभी भारत का साथ नहीं दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर भी





यूक्रेन ने सदैव पाकिस्तान का साथ दिया। यूक्रेन पिछले तीन दशकों में पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश है। इस वक्त भी वह फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च ट्रांसफर करने और उसमें नए आविष्कार करने की दिशा में पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। अतः ऐसे तथाकथित मानवतावादी लोगों को यह अवश्य समझना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करता है, आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का हमदर्द बनता है - वो देश कभी भी भारत का हितैषी नहीं बन सकता। क्या नेहरू के भारत की तरह ही हिन्दी चीनी भाई-भाई की गलती फिर से दोहरानी चाहिए या इतिहास से सबक लेकर ऐसे देश के विरोध में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को देखते हुए यदि सीधे नहीं जाना हो तो तटस्थ रहकर भारत को अपना रुख स्पष्ट रहकर देना चाहिए कि भारत रूस के साथ है। यही कारण है कि भारत, यूरोपियन देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद, रूस से प्रचुर मात्रा में तेल की खरीददारी कर रहा है। इसके साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस की खिलाफत नहीं कर रहा है।

यह बात सही है कि वैश्वीकरण के इस युग में भारत अमेरिका या पश्चिमी देशों से अपने संबंध नकार नहीं सकता किंतु रूस के साथ अपने संबंधों के मसले पर किसी भी प्रकार का समझौता करना भारत के हित में कदापि नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को सही ठहराता है। वास्तविकता तो यह है कि भारत विश्व के किसी भी कोने में हो रहे युद्ध को सही नहीं ठहराता। तभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। आज दुनिया परमाणु हथियारों के जखीरे पर बैठी है। युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, परमाणु हथियारों के प्रयोग का खतरा तो बना ही रहता है और यदि परमाणु हथियारों का

प्रयोग होता है तो धरती का विनाश अवश्यभावी है। स्पष्ट है कि भारत विश्व शांति का समर्थन करता है। सतही तौर पर रूस यूक्रेन से लड़ रहा है किंतु यह सर्वविदित है कि यूक्रेन रूस का सामना नाटो देशों द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों से ही कर पा रहा है। परोक्ष रूप से यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच में है और शिकार बन रही है निर्दोष जनता ! इसके अतिरिक्त एक खतरा और मंडरा रहा है - रूस यूक्रेन युद्ध कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। आज दुनिया के अधिकतर देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। छोटे से छोटे युद्ध की चिंगारी विश्व युद्ध को भड़का सकती है। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य अत्यंत सटीक व सार्थक है कि आज का युग युद्धों का युग नहीं है और इसे विश्व के सभी देशों को समझना चाहिए। आज का युग कूटनीतिक संबंधों का युग है, परस्पर सहयोग व वार्तालाप का युग है, परस्पर सम्मान व विश्वास का युग है। आवश्यकता इस बात की है कि रूस यूक्रेन समस्या का समाधान कूटनीतिक प्रयासों द्वारा हो, शांतिपूर्वक साधनों से हो न कि हथियारों के प्रयोग से।





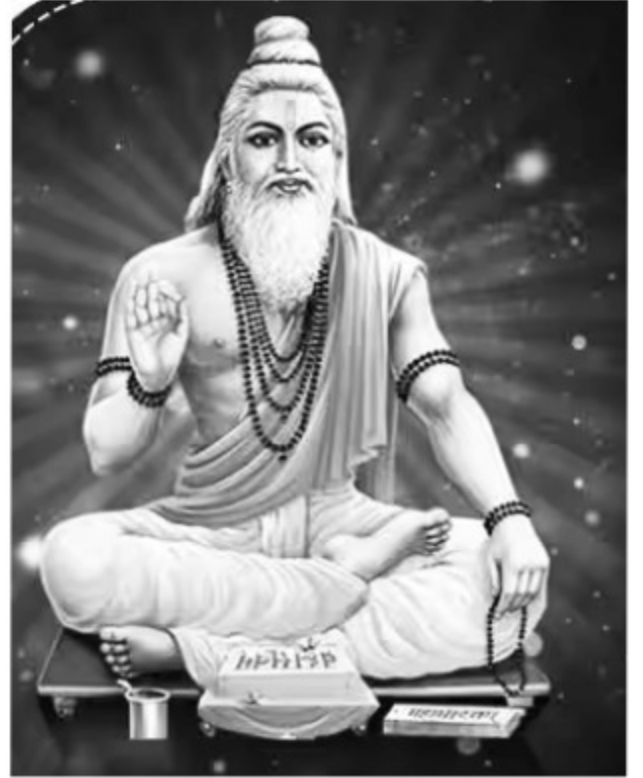
# गुरु पूर्णिमा : सबके अपने प्रतीक कहीं ध्वज तो कहीं ग्रंथ



रमेश शर्मा  
वरिष्ठ पत्रकार

गुरु पूर्णिमा अर्थात् अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। जो हमें आत्मबोध, आत्मज्ञान और आत्म गौरव का भान कराकर हमारी क्षमता के अनुरूप जीवन यात्रा का मार्गदर्शन करें वे गुरु हैं। वे मनुष्य भी हो सकते हैं अथवा ज्ञान दर्शन कराने वाला कोई अन्य प्राणी, दृश्य, घटना, ग्रंथ या ध्वज जैसा कोई प्रतीक भी। अपने इस ज्ञान दाता के प्रति आभार और उनके द्वारा दिये गये ज्ञान से स्वयं के साक्षात्कार करने की तिथि है गुरु पूर्णिमा।

देव शयन के बाद गुरु पूर्णिमा पहला बड़ा त्यौहार है जिसे पूरे भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक तीज त्यौहार के लिये तिथि का निर्धारण साधारण नहीं होता। प्रत्येक तिथि का अपना संदेश होता है उसी प्रकार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का भी एक संदेश है। इसका निर्धारण एक बड़े अनुसंधान का निष्कर्ष है। वर्ष में कुल बारह पूर्णिमा आती हैं। इन सभी पूर्णिमा में केवल आषाढ़ की पूर्णिमा ऐसी है जिसमें चंद्रमा का शुभ्र प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता या सबसे कम आता है। वर्षा के बादल चंद्रमा के प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। यद्यपि आश्विन मास की पूर्णिमा सबसे थवल होती है। यदि गुरु का संबंध मात्र ज्ञान और प्रकाश से होता तो आश्विन मास की शरद पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना जा सकता था लेकिन इसके ठीक विपरीत आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना। जिस प्रकार आषाढ़ की पूर्णिमा को चन्द्र प्रकाश को रोकने वाले बादल स्थाई नहीं होते, अवरोध मौलिक नहीं कृत्रिम होते हैं, जो समय के साथ छंट जाते हैं ठीक इसी प्रकार मनुष्य की आँखों पर अज्ञान के बादल छाये रहते हैं। भीतर आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जो ज्ञान और प्रकाश का पुंज है पर मनुष्य का अज्ञान, अशिक्षा और भ्रांत धारणाओं की परतें आत्मा के ज्ञान को ढंके रहती जिस प्रकार पवन देव बादलों को उड़ा ले जाते हैं, धरती और चन्द्रमा के बीच का अवरोध समाप्त कर देते हैं उसी प्रकार मनुष्य के बुद्धि पर पड़े अवरोध स्वयं नहीं हटते उनके लिये कोई निमित्त चाहिए। जो इस अज्ञान की परत का क्षय और स्वज्ञान का भान करा सके। यह गुरु की महिमा है कि वह व्यक्ति के ऊपर से



अज्ञानता के अंधकार की परतें हटा कर उसका स्वत्व से साक्षात्कार कराता है। आषाढ़ की पूर्णिमा इसी का प्रतीक है।

गुरुत्व परंपरा में एक बात और महत्वपूर्ण है। शिक्षक, आचार्य और गुरु में अंतर है। शिक्षक गुरु तुल्य तो होता है पर गुरु नहीं। शिक्षक अस्थायी होते हैं। आचार्य पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षा ही देते हैं। अपनी ओर से कुछ नया नहीं जोड़ते लेकिन गुरु पहले शिष्य की प्राकृतिक प्रतिभा, क्षमता, रुचि का आकलन करते हैं, उसकी मौलिक प्रतिभा को जाग्रत करते हैं फिर उसके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों को अलग-अलग अस्त्र शस्त्र में प्रवीण बनाया था। यह उनकी रुचि और प्राकृतिक क्षमता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया था। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा में विशिष्ट बनाती है। व्यक्ति की यह मौलिक प्रतिभा क्या है, क्षमता, मेधा और प्रज्ञा कैसी है। इसका आकलन गुरु करते हैं, उसका स्वत्व से साक्षात्कार कराते हैं। गुरु पूर्णिमा पर इस साक्षात्कार के लिये स्वयं को योग्य बनाने के लिये गुरु के पास जाकर आभार व्यक्त किया जाता है।





गुरु पूजन की यह परंपरा कब से आरंभ हुई यह नहीं कहा जा सकता है। भारतीय वाङ्मय में जितनी पीछे दृष्टि जाती है उतने गुरु परंपरा के आख्यान मिलते हैं। परम् गुरु भगवान् शिव को माना गया है। आदि गुरु महर्षि कश्यप, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य माने गये हैं। इसके बाद विभिन्न ऋषियों राजकुलों के गुरु के रूप में उल्लेख मिलता है।

आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु महत्ता स्थापना का पहला विवरण त्रेता युग के आरंभ में मिलता है। इसी तिथि को भगवान् शिव ने भगवान् परशुराम को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इसी तिथि से भगवान् अमरनाथ के दर्शन आरंभ होने की परंपरा भी बनी। इसी तिथि को वशिष्ठ परंपरा में महर्षि व्यास का जन्म हुआ। हमें गुरु परंपरा का उल्लेख हर युग में मिलता है।

यह ठीक है कि आरंभिक काल में गुरु परंपरा के बाहक अधिकांश ऋषिगण ही रहे हैं पर मात्र ऋषि ही गुरु बनें यह बंधन कभी नहीं रहा। पशु-पक्षी और सेवक के अतिरिक्त किसी प्रतीक जैसे यज्ञ, ग्रंथ और ध्वज को भी गुरु का मानने की परंपरा आरंभ रही है। भगवान् दत्तात्रेय के चौबीस, भगवान् परशुराम के सात, राजा जनक के तीन गुरु होने का वर्णन मिलता है। भगवान् दत्तात्रेय की चौबीस गुरु संख्या में पृथ्वी, जल, अग्नि आकाश के अतिरिक्त मधु मक्खी, कुत्ता आदि भी हैं जिनसे उन्होंने कार्य संकल्प की सीख लेने का संदेश दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने पिता महर्षि भृगु के साथ यज्ञ को भी गुरु माना। राजा जनक के तीन गुरु संख्या में प्रतीक के रूप में वेद भी गुरु हैं। ऋषिका देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि को गुरु रूप में स्वीकारा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 'ध्वज' को गुरु रूप में स्वीकारा। संघ की स्थापना के तीन वर्ष बाद आरंभ हुई यह ध्वज पूजन परंपरा पहली नहीं है। राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक ध्वज वंदन की परंपरा आचार्य चाणक्य से आरंभ हुई थी। आचार्य चाणक्य ने भगवा ध्वज को भारत राष्ट्र की पहचान और मान का प्रतीक प्रमाणित किया।

व्यक्ति, परिवार समाज और राष्ट्र संस्कृति के स्वत्व की पहचान का प्रतीक ध्वज होता है। भगवा ध्वज भारत राष्ट्र की पहचान है। भगवा अग्नि शिखा और सूर्योदय की आभा ऊषा का रंग होता है जो समता समानता का द्योतक होता है। अग्नि सभी को एकसा ताप, सूर्य सबको समान प्रकाश और ऊर्जा देता है। इसलिए भारत ने अपनी ध्वजा का रंग भगवा स्वीकार किया। ध्वज शब्द संस्कृत की 'ध्व' धातु से बनता है। इसका आशय धरती की केन्द्रीभूत शक्ति होता है। इसे धारण करने के कारण ही ऋग्वेद में धरती के लिये 'धावा' नाम आया है। राष्ट्र ध्वज से आत्मगौरव और स्वाभिमान का भी बोध होता है यह बात आचार्य चाणक्य ने कही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डा. हेडगेवार ने इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा था जो आत्मबोध कराये वह गुरु है। मनुष्य या प्राणी का जीवन तो सीमित होता है। समय और आयु अवस्था उनकी क्षमता और ऊर्जा को प्रभावित करती है। गुरु चिरजीवी होना चाहिए। अष्टावक्र से मिले आत्मज्ञान इसी भाव के अनुरूप राजा जनक ने वेद को भी गुरु तुल्य आसन दिया गुरुग्रंथ साहिब को प्राप्त गुरु स्थान की भी यही परंपरा है।

ध्वज को गुरु स्थान पर आसीन करना लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जितनी आवश्यकता आत्मज्ञान की है उससे अधिक आवश्यकता स्वत्व के बोध और राष्ट्र के स्वाभिमान जागरण की है। भारतीय ध्वज का प्रतीक कोई राजनैतिक सीमा नहीं है। यह शिक्षा संस्कार, सात्विकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत ने पूरी धरती के निवासियों को एक कुटुम्ब माना इसलिए भारत ने कभी भी, किसी भी युग में राजनैतिक या साम्राज्य विस्तार के लिये कोई युद्ध नहीं लड़ा। जो युद्ध हुये वे नैतिकता और संस्कृति की रक्षा के लिए हुये वह भी आक्रामक नहीं सुरक्षात्मक और तब हुये जब शांति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गये। ध्वज भूमि पर न गिरे इसके लिये कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दीं हैं यह हमने दाशराज युद्ध, राम रावण युद्ध, महाभारत युद्ध से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा।

कोई व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र अपने स्वत्व से दूर होकर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह भगवा ध्वज प्रत्येक भारतीय को उसके स्वत्व और स्वाभिमान का बोध कराता है। व्यक्तिगत ज्ञान के लिये भले कोई ऋषि तुल्य विभूति गुरु बनायें, दीक्षा लें पर राष्ट्र के स्वाभिमान जागरण कर्ता के रूप में ध्वज के अतिरिक्त कोई प्रतीक नहीं हो सकता इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा ध्वज को गुरु स्थान दिया और गुरु पूर्णिमा पर ध्वज पूजन परंपरा आरंभ की।

गुरु पूर्णिमा पर केवल गुरु वंदन पूजन तक सीमित न रहें। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक बार स्वयं के बारे में, अपने परिवार परंपराओं और राष्ट्रगौरव के बारे में और यदि कहीं चूक हो रही है तो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा कैसे की जाये इसका चिंतन अवश्य तभी गुरु पूर्णिमा पर गुरु वंदन पूजन सार्थक होगा।



# सेवा परमो धर्मः



**प्रशांत त्रिपाठी**

अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली

इस आधुनिक युग में जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएँ जीवन को सरल सहज बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं वहीं इसके विपरीत बहुत बार काल भी सिद्ध हुई। ऐसी ही एक भयानक त्रासदी ओड़िशा के बालासोर में 2 जून शुक्रवार को हुई। यह भीषण रेल दुर्घटना अभी तक की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। देश के बहुत से लोगों ने अपनी जाने गंवाई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए जो आज भी जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश में हुई त्रासदी उस देश के आर्थिक, सामाजिक,



राजनैतिक जीवन को प्रभावित करती है। यदि बात समूचे विश्व की करें तो चाहे विकसित देश हों या विकासशील तमाम तकनीकी प्रगतियों के बाद भी आए दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुर्घटनाओं की सुचनाएं प्राप्त होती रहती हैं जिस पर मनुष्य का नियंत्रण बहुत हद तक संभव नहीं है किन्तु एक चीज जो हमारे हाथ में है वह है मानवीय संवेदना एवं सहयोग। निश्चित रूप से ऐसी दुर्घटना किसी भी देश को आतंरिक रूप से झकझोर देती हैं किन्तु मानवीय वेदना, संवेदना एवं व्यवहार उस पर औषधि का कार्य करते हैं।

जिस देश की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो वहाँ के संसाधनों पर भी बहुत दबाव रहता है और इस प्रकार की दुर्घटना में हताहत होने वालों की संख्या भी अधिक होना स्वाभाविक है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में देश के प्रत्येक व्यक्ति की नजरें त्वरित राहत एवं बचाव पर रहती हैं जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहते हैं। घटनाओं के उपरांत आलोचना एवं दुर्घटना की समीक्षा करने के बजाय तत्काल राहत कार्यों में लगना ही मानवीय संवेदना की निशानी है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय नागरिकों की होती है। भारत में

सेवा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हमारे पूर्वजों ने इसे व्यक्ति-व्यक्ति के सुख दुःख के साथ जोड़ा है। इसीलिए जो श्रेष्ठ चिंतन हमारे पूर्वजों ने किया है उसको हम दोहराते हैं-

**सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया ।**

**सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ॥**

ऐसी परिस्थित में ध्येय वाक्य 'सेवा परमो धर्मः' के लिए संकल्पित एवं प्रतिबद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कैसे पीछे रह सकते हैं। स्वयंसेवक शब्द में ही सेवा करने का भाव आता है जो संघ के स्वयंसेवक का कर्तव्य माना गया है।

ओड़िशा के बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद एक संदेश बालासोर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक ग्रुप में भेजा गया। संदेश मिलते ही रात में ही संघ के स्वयंसेवक देवदूत बनकर यात्रियों की सहायता के लिए दुर्घटनास्थल पर पहुंचे एवं राहत कार्यों में जुट गए साथ ही जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां पास में ही संघ की शाखा लगती है। स्वयंसेवकों ने जब हादसे की आवाज सुनी तो वे त्वरित घटनास्थल पर पहुंच गए। स्वयंसेवकों ने पहले अपने वाहनों से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने से पहले ही लगभग 300-400 कार्यकर्ता लोगों की सहायता के लिए पहुंच चुके थे। धीरे-धीरे यह संख्या 600 से 800 कब हों गई पता ही नहीं चला। स्वयंसेवक दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की बोगियों में घुस-घुसकर घायलों को बाहर निकाल रहे थे। इससे पहले कि प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचती, स्वयंसेवकों ने दर्द से तड़पते घायल यात्रियों को टैपो, मोटर साईकल, कार सहित जो भी साधन मिले, उन्हें नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाना शुरू कर दिया। शनिवार की शाम तक घायलों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों ने 750 यूनिट रक्तदान कर दिया था और यह प्रक्रिया लगातार जारी रही। घायलों को ट्रेन से निकालने में कई स्वयंसेवकों ने एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया।

घटनास्थल पर पहुंचे स्वयंसेवकों को जो काम दिखा, वह उसी में जुट गए। कुछ स्वयंसेवक घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचा रहे थे तो कुछ शवों को प्लास्टिक में बांध रहे थे। अन्य स्वयंसेवक घायलों के बीच भोजन और पानी वितरण करने सहित लापता लोगों को खोजने में जुटे रहे।

कई स्वयंसेवक घायलों को खून देने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। रक्तदान करने आए युवाओं की भीड़ देखकर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैरान थे। दरअसल, बालासोर के संघ व्हाट्सएप ग्रुप में हादसे की जानकारी के साथ ही रक्तदान करने की अपील भी की गई थी। बिना किसी प्रचार-प्रसार के स्वयंसेवकों ने चुपचाप अपना सेवा कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि संघ के कार्यकर्ता समय पर नहीं पहुंचते तो मौत का आँकड़ा कहीं अधिक हो सकता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हेल्पलाइन भी शुरू की गई। प्रमुख रूप से





सेवा भारती, हिंदू जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल सहित संघ के विविध आनुषांगिक संगठन स्वतः प्रेरणा से सेवा कार्य में लगे थे। संघ के लिए इस प्रकार का सेवा कार्य करना कोई नई बात नहीं है क्योंकि संघ का यह मानना है यह समाज मेरा है और समाज का सुख-दुःख, इसकी पीड़ा मेरी है इसलिए इस समाज को सुखी करना मेरा कर्तव्य है। संघ की शाखा में यही संस्कार दिए जाते हैं। संघ अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है और इन 98 वर्षों में यह स्पष्ट रूप से दिखा है कि जब जब आपत्ति आती है, तब-तब स्वयंसेवक दौड़ कर जाते हैं। उसके लिए स्वयंसेवकों को न संकेत देना पड़ता है, न ही प्रेरित करना पड़ता है।

अभी कुछ महीने पहले जब समूचा विश्व कोरोना (Covid19) महामारी को झेल रहा था। जब अपने ही अपनों को मरता देख, उनसे दूर भाग रहें थे तब समूचे विश्व में संघ के स्वयंसेवक ही थे जिन्होंने घर-घर जाकर राशन, दवाइयां, ऑक्सीजन सहित आवश्यक वस्तुएँ पहुंचाईं।

लोगों की आलोचना सुनने के बाद भी संघ बिना किसी प्रचार या प्रलोभन के किसी भी हादसे की जगह पर निःस्वार्थ अपनी सेवाएं देना शुरू कर देता है। भूकंप, बाढ़, अकाल या कोई अन्य मनुष्य निर्मित या प्राकृतिक त्रासदी संघ के स्वयंसेवक सेवा के लिए सदैव अग्रणी रहते हैं। संघ द्वारा किए गए सेवा कार्यों की एक लम्बी सूची है उसके बावजूद भी सांप्रदायिक हिंदूवादी, फासीवादी और इसी तरह के अन्य शब्दों से पुकारे जाने वाले संगठन के तौर पर आलोचना सहते और सुनते हुए संघ को दशकों से अधिक हो चुके हैं। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना की गई होगी, वह भी बिना किसी आधार के।

आज भी कई लोग संघ को नेहरूवादी दृष्टि से देखते हैं। बताते चलें स्वयं नेहरू को भी जीते-जी अपना दृष्टि-दोष ठीक करने का एक दुखद अवसर तब मिल गया था, जब 1962 में देश पर चीन का आक्रमण हुआ था, तब देश के बाहर पंचशील और लोकतंत्र वगैरह

आदर्शों के मसीहा जवाहरलाल नेहरू न स्वयं को संभाल पा रहे थे, ना देश की सीमाओं को लेकिन संघ अपना कार्य कर रहा था। संघ के स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर रखी। जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की, तो सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। विभाजन के दंगे भड़कने पर, जब नेहरू सरकार पूरी तरह हैरान-परेशान थी, तब संघ ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए राहत शिविर लगाए। जिसके बाद जवाहर लाल नेहरू ने 1963 में 26 जनवरी की परेड में संघ को शामिल होने का निमंत्रण दिया।

कश्मीर के महाराजा हरि सिंह विलय का निर्णय नहीं कर पा रहे थे तब सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर से मदद मांगी। गुरुजी श्रीनगर पहुंचे, महाराजा से मिले। इसके बाद महाराजा ने कश्मीर के भारत में विलयपत्र का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया।

दादरा, नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका थी। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में संघ की भूमिका की याद अब भी कई लोगों के लिए ताजा है। सत्याग्रह में हजारों स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के बाद स्वयंसेवकों ने भूमिगत रह कर आंदोलन चलाए। आपातकाल के खिलाफ पोस्टर चिपकाना, जनता को सूचनाएं देना और जेलों में बंद विभिन्न राजनैतिक कार्यकर्ताओं-नेताओं के बीच संवाद सूत्र का काम संघ कार्यकर्ताओं ने संभाला। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जहाँ स्वयंसेवक स्वयं की प्रेरणा एवं संसाधनों से मात्र देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी सेवा कार्य कर रहे हैं।

पीड़ा से ही संवेदना उत्पन्न होती है, यही संवेदना व्यक्ति को सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। समाज के सशक्त और समृद्ध वर्ग को सम्पूर्ण समाज को समाज के सुख दुःख को अपना समझकर योगदान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के क्षेत्रों एवं बस्तियों में जाकर लोगों की पीड़ा को दूर करने का एक प्रयास करना चाहिए। थनोपार्जन के अतिरिक्त व्यक्ति को अपना कुछ समय सेवा कार्यों को देना चाहिए। व्यक्ति के अंदर दीन दुखियों की सेवा करने का भाव होना चाहिए, इस तरह की भावना वाला समाज ही संगठित हो पाता है। देशभर में लाखों लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, आगे भी होता रहे, यही ध्येय है।







## बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय



डॉ. पूनम कुमारी  
असिस्टेंट प्रोफेसर, आईएमएस गाजियाबाद

जनसंख्या में लगातार बढ़ती चिंता का विषय बनता जा रहा है। पूरे विश्व की आबादी आठ विलियन से भी अधिक हो चुकी है। अगर विश्व की जनसंख्या इसी रफ्तार से यूं ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास संसाधन कम और लोग ज्यादा होंगे और तब जो स्थिति पैदा होगी वह अत्यधिक भयावह होगी। बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन बार-बार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जनसंख्या को नियंत्रण में किया जा सकता है? कई कानून बनाए जा रहे हैं और कितने देशों ने तो एक या दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर दंड लगाना भी शुरू कर दिया है।

बढ़ती जनसंख्या को नजर में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1987 में हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना तथा जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करना एवं उन विषयों पर लोगों को चेताना है। परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु की सही देखभाल, मानव अधिकार का महत्व, लिंग समानता, गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल आदि के प्रति लोगो में जागरूकता फैलाना है।

सबसे अधिक चिंता का विषय यह भी है कि पूरे विश्व की आधी से अधिक आबादी एशियाई देशों में रहती है और अगर सिर्फ भारत की

बात करें तो अकेले भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, जो अब पहले नंबर पर पहुँच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (UNFPA) की रिपोर्ट के अनुसार, यह चीन की तुलना में 2.9 मिलियन ज्यादा है। वहीं, 142.57 करोड़ के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दसकों में 1.7 फीसदी बढ़ी है जबकि चीन की जनसंख्या वृद्धि पिछले दसकों में माइनस में है। यह आंकड़ा बताता है, जनसंख्या जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की भारत को कितनी ज्यादा जरूरत है। भारत की आज भी एक बड़ी आबादी भूखे पेट सड़कों पर रात बिताने को मजबूर है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन कर उभर रही है। सबसे ज्यादा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी भी भारत सहित अधिकतर एशियाई देशों में ही है।

जनसंख्या वृद्धि के कई दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता जा रहा है। बड़ी-बड़ी इमारतें बनती जा रही हैं और वन कटते जा रहे हैं, कई जंगली जीवजंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। पहाड़ों को मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने और सड़कों का निर्माण करने के लिए माईन्स लगा कर कमजोर करता जा रहे जिस कारण से पहाड़ों पर भी भूस्खलन जैसी समस्या आये दिन सुनने को मिलती है। लोग गरीबी और बेरोजगारी की वजह से चोरी डकैती जैसी घटनाएँ अकसर अखबार की सुर्खियाँ बनती रहती हैं। इन सब पर अगर रोकथाम लगाना है तो बहुत गहन होकर सोचना पड़ेगा।

भारत में हर मिनट कम से कम पच्चीस बच्चों का जन्म होता है, यह वो आंकड़ा है जो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों का है,



इसमें अभी भी घर में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या नहीं जुड़ी है। यह आकड़ा उस तस्वीर को साफ करता है जो भ्रमजाल हम पाल बैठे हैं। भगवान भरोसे न तो जनसंख्या के दर में कमी आएगी और न ही हमारे भविष्य में कोई सुधार आ सकेगा। अगर हम चाहते हैं कल हमारी आने वाली पीढ़ी इस खूबसूरत दुनिया का आनंद ले सके तो आज से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए सरकार द्वारा चलाए गए परिवार नियोजन के हर कार्यक्रम में केवल भाग नहीं लेना होगा बल्कि साथ मिल कर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना होगा।

आज भी गाँव और देहातों में अक्सर बड़ी और संयुक्त परिवार की परंपरा है जिसमें ज्यादातर घरों में कम से कम से 7 से 8 सदस्य होते हैं। उन घरों की औरतें या तो बस घरों में काम करती हैं या बाहर जाकर मजदूरी या देहाड़ी पर छोटे मोटे काम करती हैं। चूंकि परिवार बड़ा होता है और बच्चे भी ज्यादा होते हैं तो वे घरों और बाहर दोनों जगह अथाह परिश्रम करने से उनकी उम्र कम होती जाती है और वे बहुत जल्दी बुजुर्ग हो जाती हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य परिवार की कम आय की वजह से अक्सर प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषप्रधान समाज होने तथा शिक्षा के अभाव में अधिक बच्चे पैदा करने और स्त्री स्वास्थ्य

को अनदेखा करने की वजह से बहुत सी महिलाएं या तो बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती हैं या फिर बच्चा बहुत कमजोर पैदा होता है। ये बातें कहीं न कहीं हमें बताती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कोई पुख्ता कदम उठाने की बहुत जरूरत है।

बढ़ती जनसंख्या और उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए टू चाइल्ड पॉलिसी जिसका उल्लेख 2019 के जनसंख्या नियंत्रण बिल में भी है, को लाने की तरफ इशारा करता है पर कहीं न कहीं 35 बार संसद में पेश होने के बावजूद यह पॉलिसी अटक कर रह जाती है क्योंकि अगर यह कानून लागू किया जाता है तो कानून को तलाकशुदा जोड़ों के अधिकारों के साथ-साथ इस्लामी धर्म को भी ध्यान में रखना होगा। इतना ही नहीं यह भी ध्यान रखना होगा कि यह अवैध गर्भपात को बढ़ावा तो नहीं दे रहा। कोई ठोस कानून बनाने और उसे अमल में लाने से शायद जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार को भी अपने हर कार्यक्रम और योजना का शुरुआत से लेकर अंत तक समान रूप से नजर रखनी होगी। आज लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझना होगा। यह न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा।

## कथन



पूरे देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। हमारी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत पूर्ण आत्मविश्वास के साथ एक विकसित देश बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की ओर अग्रसर है।

- द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि, हमारी ये संसद ही है।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



भारत प्रगति कर रहा है, कई आंतरिक मामलों में सुधार कर रहा है। देश की अखंडता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सारा भारत हमारी मातृभूमि है। भारत में हर कोई एक विशिष्ट पहचान के साथ सुरक्षित है।

- डॉ. मोहन भागवत (सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)

भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है। जिसे रोकने के लिए तमाम विरोधी शक्तियां सामने आ रही हैं। यह वह शक्तियां हैं, जिन्हें उजाला पसंद नहीं है।

- दत्तात्रेय होसबाले (सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)





# बाघों का संरक्षण बना स्थानीय विकास का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस विशेष



प्रकाश श्रीवास्तव  
प्रकृतिविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता

सन् 2005 में मुझे सरिस्का टाइगर रिजर्व जाने का मौका मिला। सरिस्का दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए मेरे जैसे कई प्रकृति प्रेमी जब अपनी व्यावसायिक दुनिया से अधिक टाइम नहीं निकाल पाते थे और आज भी नहीं निकाल पाते हैं तो दिल्ली से सटे सरिस्का उनके लिए एक त्वरित शरण के रूप में काम आ जाता है।

जब मैं सरिस्का के स्थानीय पर्यटन ऑफिस पहुंचा तो पर्यटन ऑफिस किसी पुराने फिल्म में दर्शाये किसी वीराने गांव की याद दिला रहा था। चंद जिप्सी या सफारी चालक मिले जो कि उस वीराने का साथ ताश के पत्ते के साथ दे रहे थे। ना परमिट की समस्या थी और ना ही किसी सफारी के गाड़ी की क्योंकि मेरे अलावा उस दिन सरिस्का घूमने कोई नहीं आया था।

अब आते हैं सन् 2014 में जब मैं फिर उसी सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने पहुंचा तो आज सन् 2005 का वो वीराना गांव किसी मेले का रूप ले चुका था। आज स्थिति ये थी कि एक नहीं 50 जिप्सी सफारी चालक थे और कोई भी खाली नहीं था, समस्या यहाँ तक हो गई की मुझे एक दो अपने परिचितों को फोन लगाना पड़ गया कि मैं दिल्ली से सरिस्का आ गया हूँ और सफारी नहीं मिल पा रही है।



सन् 2005 के सरिस्का और सन् 2014 के सरिस्का में आखिर क्या अंतर था ये जानने के लिए हम थोड़ा पीछे सन् 2008 में चलते हैं।

सन् 2008 में भारत सरकार ने इतिहास में पहली बार बाघों के संरक्षण को ले कर एक सफल प्रयास किया था। ये प्रयास था 3 बाघों को रणथम्भोर बाघ आरक्षित वन से सरिस्का बाघ आरक्षित वन में पुनर्स्थापित करने का। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरिस्का के सारे बाघों को अवैध शिकारियों ने जिनको पोचर भी कहा जाता है, मार दिया था। सौभाग्य से ये प्रयास सफल रहा और ताजा आंकड़ों के हिसाब से अभी सरिस्का 28 बाघों का घर बन चुका है जिसमें की बाद में भी कई बाघों को रणथम्भोर से ला कर यहाँ छोड़ा गया।



अंतर साफ था, बाघ चले गए या मार दिए गए तो पर्यटक भी चले गए, अब बाघ वापस आ गए थे तो वो अपने साथ पर्यटकों को भी वापस ले आये थे। वन्यजीव पर्यटन में पर्यटकों की मुख्य दिलचस्पी जंगल के राजा को देखने में होती है ये बात तय थी।

वन्यजीव पर्यटन को आज अगर हम मुख्य रूप से बाघ पर्यटन कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि पूरे भारत में आज केवल वही वन्यजीव पर्यटन स्थल पर्यटन का मुख्य केंद्र बन कर उभरे हैं जिनमें कि बाघों की संख्या अधिक है।

बाघों के जंगल में दिखने की रोचकता को दोगुना उनका शर्मिला अंदाज कर देता है, उसका एक कारण है अंग्रेजी शासन काल में हुआ उनका अक्षीण शिकार जिसने की उनके मन में इंसानो का एक डर बिठा दिया है। हर कीमत पर बाघ अपने छलावरण का प्रयोग कर इंसानी नजरों में आने से बचते हैं।

ऐसे में बाघों के संरक्षण और उनसे जुड़ा पर्यटन एक दूसरे के पूरक बन कर उभरे हैं।

कहते हैं की आप उस वस्तु या स्थान या फिर जीव से कभी लगाव नहीं कर सकते हैं जिसको आपने कभी देखा या अनुभव नहीं किया है। ऐसे में बाघों के संरक्षण की तरफ एक सकारात्मक राय और



आख्यान बनाने और समर्थन जुटाने में उनसे जुड़े पर्यटन का अद्वितीय योगदान है। ये सकारात्मक राय इसीलिए भी बन पायी है क्योंकि किसी टाइगर रिजर्व से जुड़े गांव में जब वहां के स्थानीय निवासी केवल कृषि से जुड़े थे तो बाघों को एक परोपजीवी या पीड़क के रूप में देखा जाता था जो क्री समय समय पर गांव के किसानों के मवेशियों को उठा ले जाते थे।

आज समय बदल गया है और उसी गांव से बाघों के पर्यटन में कोई जिप्सी सफारी चलाता है, कोई गाइड बन गया, कुछ प्रशासन का हिस्सा बन गए हैं, कई गांव वालों ने अपनी अपनी जमीनों पर होटल खोल लिए हैं और पर्यटन व्यवसाय से जुड़ने के कारण



बाघों के संरक्षण से भी जुड़ गए हैं। क्योंकि अगर बाघ नहीं रहेंगे तो पर्यटक भी नहीं आएंगे ये बात अब सभी को समझ आ चुकी है।

पर्यटन का बाघों के संरक्षण में योगदान केवल मूर्त लाभ के रूप में नहीं बल्कि अमूर्त लाभ के रूप में भी होता है।

किसी टाइगर रिजर्व में जब सुबह शाम बाघों की तलाश में पर्यटक निकलते हैं तो एक अप्रत्यक्ष रूप से वो उसी जंगल की पेट्रोलिंग भी कर देते हैं जिसके कई फायदे सामने आये हैं।

ऐसा कई बार हुआ है कि जंगल में घुसे अवैध लोगों को पर्यटकों ने देखा है और उसकी खबर तुरंत प्रशासन को दी है। कई मामले ऐसे भी आये हैं जिसमें की पर्यटकों ने किसी मृत बाघ को ढूँढ निकाला है जिसकी हत्या या पोचिंग कर दी गयी थी। पर्यटकों का किसी भी अभ्यारण में होना वहां की समस्त प्रशासनिक कार्य पद्धति के सरकारी तंत्र में एक पारदर्शिता लाती है क्योंकि अगर किसी टाइगर रिजर्व में कई दिनों तक बाघ नजर नहीं आते हैं तो ये बात स्थानीय प्रशासन के अलावा दिल्ली तक पहुंचाने में अधिक समय नहीं लगता है और इसके मुख्य स्रोत भी पर्यटक होते हैं।



फिर ऐसे में यहाँ ये बता देना भी आवश्यक हो जाता है कि अधिकतर बाघों की पोचिंग के मामले जो सामने आये हैं वो बरसात के मौसम में आये हैं जब टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिए बंद हो जाता है। ये सिद्ध हो चुका है कि अवैध शिकारी बाघों के अवैध शिकार को अधिकतर अंजाम बरसात के मौसम में या फिर पर्यटन के ऑफ सीजन में देते हैं।

पर्यटकों की गतिविधि और उनकी संख्या को प्रशासन नियंत्रित करता है जो की एक बहुत अच्छी बात है। पर्यटकों के लिए कई कड़े और महत्वपूर्ण नियम बनाये गए हैं जैसे की कोई कचरा बाहर नहीं फेकना, शोर नहीं मचाना, गाडी से नीचे नहीं उतरना जिससे की पर्यटक और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रहते हैं।

पर्यटकों को भी जिम्मेदारी से, प्रशासन द्वारा बनाये गए पर्यटन से जुड़े सभी नियम व कानूनों का पालन कर प्रकृति का आनंद लेना चाहिए और इस पूरे संरक्षण चक्र का एक सकारात्मक हिस्सा बनना चाहिए।

एक अनुमान के हिसाब से 1 पर्यटक किसी बाघ अभ्यारण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 11 लोगों के रोजगार का कारण बनता है और एक बाघ अभ्यारण औसतन 20000 परिवारों का पालन पोषण करता है।

देवभूमि उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रति वर्ष औसतन 4 लाख पर्यटक इसलिए आते हैं क्योंकि वहां 250 से अधिक बाघ हैं और पिछले पांच वर्षों के आधिकारिक राजस्व के आंकड़े वहां पर बाघों के हुए अच्छे स्तर के संरक्षण के कारण हुए पर्यटन की अपार सफलता की कहानी स्वयं बयान करते हैं।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व	
वर्ष	राजस्व जमा (धनराशि लाख में)
2018-19	155.95
2019-20	1112.78
2020-21	846.15
2021-22	1038.95
2022-23	1442.61

आंकड़े साफ बताते हैं, जहाँ बाघ हैं पर्यटक वही जायेंगे। जिन्होंने भी अपने यहाँ बाघों के संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी आज वो इस नए युग के संरक्षण के बीज से उपजे सबसे सुन्दर फल का आनंद नहीं ले पा रहे हैं।

किसने सोचा था की किसी समय बाघों के धिनौने शिकार का खेदजनक केंद्र रहा भारत आज विश्व में बाघों की राजधानी बनकर उभरेगा और किसने सोचा था किसी समय बाघों के विनाश के लिए मिल रहे उस आधिकारिक अनुज्ञा-पत्र से कहीं अधिक ताकतवर आज बाघों के संरक्षण से जुड़े अनुज्ञा-पत्र साबित होंगे।



# डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का स्वर्णिम भविष्य

## यह समय है नैरेटिव बदलने का, लाइट, कैमरा, टेक एक्शन



आशीष कुमार 'अंशु'  
स्वतंत्र लेखक

वृत्तचित्र को हम अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसी व्यक्ति, संस्था, समाज, संस्कृति, स्थान, देश, क्षेत्र या किसी भी अन्य विषय के बारे में दी गई प्रामाणिक जानकारी का माध्यम है। इस प्रामाणिक जानकारी की प्रस्तुति के लिए इसमें संदर्भ सामग्री का उल्लेख, साक्षात्कार, वाइस ओवर, वृत्तान्त, संगीत एवं ध्वनि प्रभावों का सुविधानुसार उपयोग किया जाता है। जिस विषय पर फिल्म बनाने के लिए काम किया जा रहा है, उस विषय पर फिल्मकार ने कितना अध्ययन किया है। उस बात का अनुमान फिल्म को देखकर उसके दर्शक लगा लेते हैं। मसाला फिल्मों से अलग डॉक्यूमेंट्री फिल्म के दर्शक होते हैं। आम तौर पर वे सिनेमा की समझ रखने और पढ़ने लिखने में रुचि लेने वालों का वर्ग है। इसलिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाते हुए, स्क्रिप्ट पर अधिक मेहनत करनी चाहिए क्योंकि उसी पर पूरी फिल्म को खड़ा होना है। पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण ही स्क्रिप्ट पर निर्भर करेगा। यदि कहें कि डॉक्यूमेंट्री से डॉक्यूमेंट्री शब्द बना है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब दस्तावेज और दस्तावेजीकरण। इस तरह आपकी फिल्म आने वाले समय में अपने विषय का दस्तावेज नहीं बन सकता तो वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं मानी जाएगी। आप फिल्म का विषय जैसा चाहे वह रख लीजिए लेकिन उसमें इस्तेमाल की जा रही सामग्री चित्र, दृश्य और ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत किया गया दस्तावेज होना चाहिए। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में सिर्फ मनोरंजन का माध्यम भर नहीं है। यह जागरूकता और समाज को शिक्षित करने के लिए भी है।

पिछले कुछ समय से व्यक्ति परक, सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में समाज की रुचि बढ़ी है। केरला स्टोरिज (2023), कश्मीर फाइल्स (2022), द ताशकंद फाइल्स (2019) जैसी मुख्य धारा की बनी फिल्में भी 'डॉक्यूमेंट्री' महत्व की फिल्में रहीं। बीते सात आठ सालों में नए नैरेटिव के साथ फिल्मों का एक बड़ा बाजार निर्मित हुआ है। सच्चाई यही है कि दर्शकों से इस देश में डॉक्यूमेंट्री के नाम पर एनजीओ और कांग्रेसी इको सिस्टम के वामपंथी संगठनों द्वारा प्रोपगेन्डा बनाकर परोसा जाता था। यह सब इस देश में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ। इसके लिए कांग्रेस की सरकारों ने

फिल्मकारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई, वामपंथी संगठनों ने कन्टेंट पर काम किया और अपने ही लोगों से फिल्में बनवाई। उन फिल्मों में जाति के नाम पर आपसी टकराव को खूब उभारा गया। वहीं दूसरी तरफ हिन्दू मुस्लिम एकता को साबित करने पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कांग्रेस की वामपंथी फिल्म लॉबी के काम काज में यह विरोधाभास साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो कॉमरेड हिन्दू मुस्लिम एकता की तख्ती लेकर प्रेम की दुकान चला रहे थे। वही लोग जाति के नाम पर समाज में नफरत भी बो रहे थे। जावेद अख्तर और अमजद खान की फिल्मों में नमाज पढ़ने वाला आज तक धूर्त नहीं दिखाया गया। वह सच्चा मुसलमान था। ब्राम्हण धूर्त और दूसरी स्त्रियों पर बुरी नजर रखने वाला होता था। भारतीय समाज ने दशकों से यही सब फिल्मों में देखा। सन्यासी को बलात्कारी दिखाने वाली वेबसीरीज 'आश्रम' को सच्ची घटना पर आधारित कहकर ही प्रचारित किया गया। एमएक्स प्लेयर पर उसका तीसरा सीजन चल रहा है। दूसरी तरफ अजमेर सेक्स स्कैंडल पर बन रही फिल्म अजमेर 92 का अभी से विरोध हो रहा है। उस सेक्स स्कैंडल के तार अजमेर की दरगाह और कांग्रेस के नेताओं से भी जुड़ते हैं। जहां अपराधी मुसलमान और पीड़ित लड़कियां बड़ी संख्या में हिन्दू थीं। पूरे मामले को कांग्रेस की सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दबाया। बताया जाता है कि उस सेक्स स्कैंडल की चपेट में कई हजार लड़कियां आई थीं। यह सेक्स स्कैंडल इतना बड़ा बन गया कि 90 के दशक में अजमेर में लड़कियों की शादी में मुश्किल आने लगी। बेटियों को परिवार के लोग संदेह की नजर से देखने लगे थे। अजमेर 92 सिर्फ एक उदाहरण है। हमारी संस्कृति, इतिहास, समाज से जुड़ी ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। जिसे कांग्रेस की सरकार की सरपरस्ती में अंजाम दिया गया। उन कहानियों को सामने लाने में डॉक्यूमेंट्री फिल्में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। इनका बजट कम होता है और यह फिल्में समाज को दिशा दिखाने में 'जागरण श्रेणी' का काम करती हैं।

कांग्रेस की संरक्षण की वजह से इप्ता (इंडियाज पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन) के लोग फिल्म इन्डस्ट्री में भरे हुए थे। संस्कार भारती के साथ वहां असुश्यता का व्यवहार किया जाता था। सिर्फ फिल्म नहीं, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता सभी के प्रवेश द्वार पर वामपंथी दरबान कांग्रेस ने लगाए हुए थे। उन दरवाजों से वामपंथियों का प्रवेश सबसे सुगम तरीके से होता था। इस तरह विद्यार्थी जीवन में अभिनय, साहित्य, कला, इतिहास, संगीत से जुड़ाव महसूस करने वाले छात्र दरवाजे पर ही पकड़ कर वाम की तरफ मोड़ दिए जाते रहे। अब पीयूष मिश्रा जैसे वामपंथियों के बीच से निकल आए कलाकार ही कह रहे हैं कि कम्युनिस्टों ने सिखाया कि मां गंदी चीज है, बाप गंदी चीज



है, परिवार गंदी चीज है। उन्होंने शराब की लत लगाई। उन लोगों ने जिन्दगी के बीस साल खराब किए। पीयूष एक साक्षात्कार में बताते हैं कि मां बाप वामपंथियों के समाज का हिस्सा नहीं होते। उनका समाज मां बाप विहीन समाज है। कम्युनिस्ट का मतलब है खराब बेटा। खराब पति। खराब बाप।

एनएसडी से संबंध रखने वाले एक अभिनेता ने बताया कि वह एक थिएटर समूह से जुड़ा। वहां एक क्रिश्चियन निर्देशक की देखरेख में वे लोग एक नाटक की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच माता के नवरात्रे आ गए। एक दिन वह घर से पूजा के बाद रिहर्सल में तिलक लगाकर आ गया तो थिएटर समूह के दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। तिलक लगाने भर से उसे संधी और बजरंगी कहने लगे। जबकि उसी थिएटर समूह में रोजा के दौरान शाम को सभी मिलकर इफ्तार में शामिल होते थे। 25 दिसम्बर की केक भी वहां आती थी। उसे समझ नहीं आया, फिर नवरात्रों के प्रसाद और तिलक से समूह के लोगों में इतनी नफरत क्यों थी?

यह नफरत थोड़ी सी मेहनत से डिकोड भी हो गई। वास्तव में यह वही नफरत थी, जिसे योजनापूर्वक कांग्रेसी इको सिस्टम के वामपंथी सिपहसालारों ने कला, संस्कृति, साहित्य और अकादमिक क्षेत्र में फैलाया है। इसी इको सिस्टम ने शुभमश्री की देवी सरस्वती को अभद्रतापूर्वक चित्रित करती तुकबंदी को महान कविता कहकर



सम्मानित कराया। इसी इको सिस्टम ने अपनी मां की तस्वीर सिर से पैरों तक ढक कर बनाने वाले मकबूल फिदा हुसैन को उस वक्त का महान चित्रकार कहकर प्रचारित किया, जब उसने करोड़ों हिन्दुओं की मां देवी सरस्वती की न्यूड तस्वीर बनाई थी। यही इको सिस्टम था जो हिन्दू मुस्लिम एकता की बात खूब करता लेकिन कभी दलित सवर्ण प्रेम को लेकर आगे नहीं बढ़ा। उसकी कोशिश रही कि हिन्दू समाज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य पिछड़ा जैसे दर्जनों वर्गों में बंट जाए। डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने वाले नए रंगरूटों के लिए हजारों विषय हैं और अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में।

भारत में दशकों से एक खास तरह के नैरेटिव के साथ फिल्में बनती रही हैं। इन दिनों 'द केरला स्टोरी' के ऐतिहासिक प्रयास को अफवाह फैलाकर कम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि समाज में घटी हुई घटनाओं को केन्द्र में रखकर फिल्म बनाने का एक लंबा इतिहास है। वामपंथी एजेन्डे को पुष्ट करने वाली कुछ फिल्मों के नाम यहां दे रहे हैं।

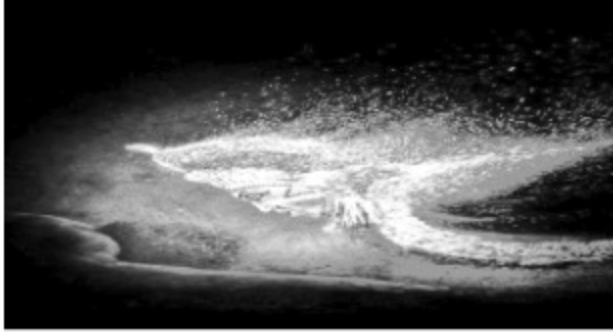
- ◆ बाबू जनार्दन की मलयालम फिल्म बॉम्बे मार्च 12 | 2011 | मुम्बई 93 दंगे पर
- ◆ मणीरत्नम की बॉम्बे | 1995 | मुम्बई 93 दंगे पर
- ◆ अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे | 2004 | मुम्बई 93 दंगे पर
- ◆ निशिकांत कामत की मुंबई मेरी जान | 2008 | 11 जुलाई 2006 को मुम्बई में हुए ट्रेन ब्लास्ट पर
- ◆ राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'द अटैक्स ऑफ 26 / 11' | 2013 | 2008 में मुम्बई में हुए धमाकों पर आधारित
- ◆ 2017 में आई राहुल डोलकिया की फिल्म 'रईस' में गुजरात दंगों का जिक्र मिलता है
- ◆ गोपाल मेनन की फिल्म 'हे राम: जेनोसाइड लैंड आफ गांधी
- ◆ 2013 में आई 'काय पो चे' में भी गुजरात दंगे हैं
- ◆ 2008 में नंदिता दास की 'फिराक' आई। गुजरात दंगों के असर पर फिल्म है
- ◆ 2007 में आई राहुल डोलकिया की फिल्म 'परजानिया'। जिसमें गुजरात दंगों में खोए हुए एक लड़के की कहानी है
- ◆ 2004 में राकेश शर्मा ने गुजरात दंगों पर बनाई 'फाइनल सलूशन'
- ◆ 2005 में 'चांद बुझ गया' बनी। जिसे अपने कन्टेन्ट की वजह से सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला
- ◆ मनोज कुमार की 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी फिल्म 'मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव' | 2017 |
- ◆ मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी व्यास वर्मा की फिल्म 'शोरगुल' पर फतवा जारी कर दिया गया था। इसमें मुख्य भूमिका जिमी शेरगिल ने निभाई है।



# कला (सिनेमा) के क्षेत्र में भारत का अभ्युदय

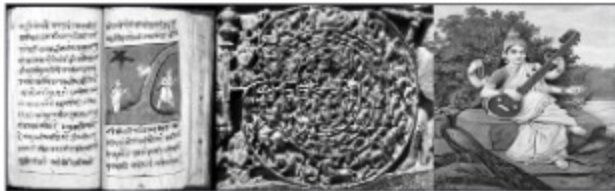


अथर्व दयाल शर्मा  
युवा लेखक



**सभ्यता का स्तोत्र :** अनादि काल से भारत ने कहानी कहने की कला में अपने दिव्य तरीके से दक्षता हासिल की है। नाट्यम, नृत्यम, संगीतम के साथ-साथ शिल्पकला, साहित्यिक कृतियों और चित्र कला के आकर्षक संयोजन को महान महाकाव्यों और इतिहास को सामान्य रूप से चित्रित करने के लिए अच्छी तरह से सम्मिलित किया गया है।

ऋषि भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्रम (संस्कृतम में प्रदर्शन कला पर एक विस्तृत ग्रंथ) और विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से हैं, जहां तक साहित्यिक कार्यों का संबंध क्रमशः कला और कहानी कहने से है। इसकी बहुलतावादी और समावेशी प्रकृति के कारण, भारत पर हुए आक्रमणों से पूर्व विश्व पर सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध था।



**वैचारिक तोड़फोड़ :** जैसे ही विदेशी आक्रमणकारियों और उपनिवेशवादियों ने भारत की पवित्र भूमि पर विध्वंस किया, इसकी संस्कृति को भी नष्ट कर दिया गया। वैचारिक विध्वंस के एक हिस्से के रूप में, साहेबों का एक समूह बनाया गया था और देशी संस्कृति का शिकार करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया था। सिनेमा पर कब्जा करते ही सामान्य जनमानस से भारत को भुला दिया गया।

एक उद्योग जो उत्तर-औपनिवेशिक अपराधबोध और स्वदेशी संस्कृति के प्रति घृणा के दृष्टिकोण से आगे निकल गया था, अब भारत को बहिष्कृत करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ जनता तक पहुंच गया

था। बॉलीवुड ने लगभग सात दशकों तक अभियान का नेतृत्व किया और यह हम भारत के लोग थे जिन्होंने उन्हें वित्त पोषित किया। भारतीयता को जनता के बीच जगह नहीं मिली और शहरी नक्सलियों द्वारा जब भी उनके पास कुछ प्रस्तुत करने के लिए पहुंचा उसे रद्द कर दिया गया। मनोरंजन के नाम पर भारत पर बदनामी, शत्रुता और घृणा फेंकी गई।

**भारत का पुनरुत्थान :** लेकिन आगमन और अस्तित्व के संघर्ष को केवल सितारों के संरक्षित होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। धर्म के केंद्र में आने के साथ धैर्य और दृढ़ता सफलता की कुंजी थी।

2014 ने देश के मिजाज में बदलाव देखा और बाद में मनोरंजन उद्योग के मामले में भी ऐसा ही हुआ। प्रचार, साहित्यिक चोरी, भाई-भतीजावाद, लोकवाद और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीयों द्वारा उन्हें फासीवादी और असहिष्णु करार दिए जाने की कीमत पर अस्वीकार कर दिया गया था। भारतीयों के एक झुंड और कुछ साक्षियों के बीच का बड़ा झगड़ा अब बढ़ गया था।

निम्नलिखित फिल्मों में भारतीय पहलुओं का वर्णन कैसे किया गया, जो अंततः ब्लॉकबस्टर हिट बन गईं।



1.) **कांतारा :** यह फिल्म दाइवाराधने / भूतकोला जैसी गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक जड़ों को श्रद्धा और अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करती है। भारत भर में फैले क्षेत्रों और क्षेत्रपालों के बीच पवित्र संबंध को सौंदर्यपूर्ण रूप से चित्रित किया गया है। इसके अलावा, कंबाला (मवेशी दौड़) को खूबसूरती से भारत के डेयरी आधारित सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर प्रकाश डाला गया है। फिल्म धीरे-धीरे भारत में मानव-प्रकृति संघर्ष की अनुपस्थिति पर आगे बढ़ती है और इसे औपनिवेशिक आयात के रूप में कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वराह रूपम, कर्नाटक संगीत का एक आदर्श मिश्रण विशेष रूप से बताता है कि कैसे ग्राम देवता प्रतीकात्मक रूप से परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और पूरे भारत में लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। इस प्रकार, इन क्षेत्रों की अपनी अलग संस्कृति है और फिर भी सनातन धर्म की छत्रछाया में आते हैं। इस प्रकार भारत अनादि काल से अनेकता में एकता का उत्सव मनाता आया है।





2.) दि कश्मीर फाइल्स : जब कोई द कश्मीर फाइल्स के बारे में सोचता है तो क्रूर, अप्राप्य या दिल तोड़ने वाली तत्काल प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के वीभत्स दृश्यों के अलावा, फिल्म सूक्ष्म रूप से कश्मीर के धार्मिक पक्ष को दर्शाती है। कृष्ण पंडित के रूप में दर्शन कुमार के एकालाप में कश्मीर के गौरवशाली लेकिन कठिन इतिहास को छुआ गया है।

जिस तरह महर्षि कश्यप, चरक, विष्णु शर्मा, शंकराचार्य जैसे पंडितों से लेकर ललितादित्य मुक्तापीड जैसे सम्राटों ने कश्मीर को सभ्यताओं का पालना बनाया और फिर भी भुला दिया गया। ऐसा लगता है कि निर्माताओं ने पवित्र भूमि की अविभाज्य और अंतर्निहित शैव प्रकृति को उजागर करके भारत की भावना पर अपनी नब्ज पकड़ ली है। ज्ञान का केंद्र होने के नाते सरस्वती आराधना सर्वत्र प्रदर्शित है।

“तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में!” यह वाक्य हमें सोचने पर विवश कर देता है।



3.) बाहुबली : एस.एस. राजामौली की मैग्निम ओपस महाभारत से प्रेरित प्रतीत होती है और कुशलता से भारत की संस्कृति को पूर्ण महिमा में प्रस्तुत करती है। फ्रेंचाइजी ने चतुराई से तैयार की गई कहानी में क्षात्र तेज और राजधर्म को अलंकृत किया। महिष्मती की एक झलक आँखों में चमक भर देती है।



4) कुछ अन्य फिल्मों जैसे आरआरआर, कार्तिकेय 2, राम सेतु और रॉकेट:नाम्बी इफेक्ट भी दिल और दिमाग को सही जगह पर रखने के उनके प्रयासों में सहायक रही हैं। रामम राधवम, कृष्णा ट्रान्स और श्री वेंकटेश्वर सुप्रभातम समृद्ध और मधुर हैं।

सोशल मीडिया ऐप्स के अभूतपूर्व उदय के साथ, YouTube धार्मिक / भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक मंच के रूप में उभरा।

### 1) द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक

: गहन शोध के साथ, वृत्तचित्र का उद्देश्य भारत को बिना किसी गलती के किए गए विश्वासघात को प्रस्तुत करना है। जिस तरह से हुकड क्रहस को जानबूझकर स्वास्तिक के रूप में बदनाम किया गया था, उसे साहसपूर्वक फिल्माया गया और सार्वजनिक जांच के लिए रखा गया।



भारत का इतिहास धर्म की भूमि की रक्षा के लिए बहादुर प्रतिरोध और बलिदान से भरा है, लेकिन फिर हम क्यों गिरे? हम आक्रमणकारियों से नहीं हारे, लेकिन साहेबों ने उन्हें छोड़ दिया। डॉक फिल्म इतिहास के इस खंड की सच्चाई और अनकही कहानी को उजागर करती है।

### 3) तेनाली आर.के :

एक वेब कथा जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति की मदद से कृष्णदेव राय को समकालीन दुनिया से जोड़ने वाली एक काल्पनिक कहानी को गढ़ती है, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का केंद्रीय संदेश देती है।



भारत की आत्मा जीवित है और पवित्र भूमि पुनर्जीवित होने के लिए तैयार है।



# फिल्म उद्योग को भा रहा जम्मू कश्मीर



**डॉ. विनीत उपपल**  
असिस्टेंट प्रोफेसर, भारत जन संचार संस्थान, जम्मू  
एवं समन्वयक, डिजिटल मीडिया कोर्स

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर लुभा रहा है। यहाँ करीब तीन सौ से अधिक फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनने वाली सीरीजों की शूटिंग हो रही है। नए-नए लोकेशन ढूँढे जा रहे हैं और उनकी जानकारी फिल्मकारों के साथ-साथ आम जनता को मुहैया कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर फिल्म विकास परिषद् (जेकेएफडीसी) का गठन किया है और इसके पोर्टल के जरिये दुनिया भर के फिल्मकारों को करीब 1500 से अधिक स्थानीय अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, कलाकारों, कला निर्देशकों, कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर, निर्देशक, डांसर, लोकेशन मैनेजर, मॉडलिंग एजेंसी, प्रोड्यूसर, गायक आदि से संपर्क साधने और काम देने का मौका मिल रहा है। राज्य सरकार की पहल पर राज्य के करीब 250 विभिन्न स्थानों की जानकारी के साथ-साथ तुरंत ऑनलाइन बुकिंग कराने का मौका भी फिल्मकारों को पोर्टल के जरिये मिल रहा है। इन स्थानों में किला, गोल्फ कोर्स, झील, बांध, जलप्रपात, घास के मैदान, घाटी, संग्रहालय, महल, पार्क, धार्मिक स्थल, बर्फबारी वाले स्थल, हिलटॉप आदि शामिल हैं।

जी-20 सम्मलेन के तुरंत बाद श्रीनगर में 26 मई को कश्मीरी निर्माता-निर्देशक की बनाई फिल्म 'वेलकम टू कश्मीर' का प्रीमियर हुआ। बीते 34 वर्ष के दौरान आम कश्मीरियों की जिंदगी पर आधारित यह फिल्म थी और इसमें अभिनय करने वाले मुख्य कलाकार भी कश्मीरी थे। राज्य के सोपोर के पास के गांव के तारिक बट इस फिल्म के निर्देशक हैं और यह फिल्म श्रीनगर के आइडॉक्स सिनेमा में दिखाया गया था। जम्मू कश्मीर फिल्म नीति-2021 के लागू होने के बाद तो राज्य का परिदृश्य ही बदल चुका है। स्थानीय लोगों का टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। क्षेत्रीय भाषा और कम बजट वाली फिल्मों की शूटिंग हर जगह जमकर हो रही है। दिन-रात फिल्म निर्माण का कार्य चल रहा है। फिल्म की नीति को वर्ष 2026 तक ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में फिल्म शूटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को मुफ़ीद जगह बनाने, अधिक से अधिक स्थानीय कलाकारों को अपने टैलेंट दिखाने और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने, राज्य की कला, संस्कृति, इतिहास और परम्पराओं को सामने लाने की है। यहाँ शूटिंग को बढ़ाने और फिल्मकारों को आकर्षित करने की पहल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रयासों से हुई, जिस कारण कश्मीर की हसीं वादियों में शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट

आदि अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए आ चुके हैं।

कश्मीर फिल्म विकास परिषद् (जेकेएफडीसी) की स्थापना जम्मू कश्मीर के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अंतर्गत किया गया। फिल्म प्रभाग के जरिये लघु और शिक्षाप्रद फिल्मों को राज्य के विभिन्न सिनेमाघरों में दिखाए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न उपकरण भी आसानी से उपलब्ध कराये जाने की योजना को अमलीजामा पहनाने का कार्य चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विशेष ब्रांडिंग जैसे विषय पर फिल्में बनाता है तो उसे निर्माण में होने वाले खर्च का 50 फीसदी यह पांच करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान जम्मू कश्मीर फिल्म नीति-2021 में है। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' जैसे विषयों सहित बच्चों व महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर बनने वाली फिल्मों को भी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पुरस्कृत फिल्मकारों को भी विशेष सब्सिडी प्रदान करने की योजना पर कार्य राज्य सरकार कर रही है।

जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार



किस तरह सजग है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 तक पांच सौ करोड़ रुपये का बजट रखा है। राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के निर्माण में छूट प्रदान की जा रही है। फिल्म सिटी से लेकर स्टूडियो के निर्माण में भी आर्थिक सहायता मिल रही है।

बंद पड़े सिनेमाघरों का पुनरुद्धार किया

जा रहा है। मौजूदा सिनेमाहाल को अपग्रेड किया जा रहा है। नए मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हाल के निर्माण करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तो और जम्मू कश्मीर फिल्म आर्काइव का गठन किये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे फिल्मों का डेटाबेस तैयार हो। साथ ही, संबंधित पोर्टल पर राज्य में शूट की गई फिल्मों की जानकारी भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुंबई दौरे में फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के साथ विचार-विमर्श और सुझाव के बाद जम्मू कश्मीर में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर फिल्म नीति-2021 तैयार की गई थी।

साठ के दशक से लेकर आज तक दुनिया भर के फिल्मकारों को जम्मू कश्मीर लुभा रहा है। शम्मी कपूर और नंदा का रोमांस हो या शाहरुख खान व कैटरीना कैफ की जोड़ी, दुनिया भर के लोगों ने बड़े परदे पर जम्मू-कश्मीर की वादियों में ये हसीन दृश्य देखे। वर्ष 1960 के दशक में 'कश्मीर की कली', 'जब-जब फूल खिले', 'हिमालय की



गोद में', 'जानवर' जैसी फिल्मों की शूटिंग श्रीनगर और गुलमर्ग में हुई थी। 1973 में आई सुपरहिट फिल्म 'बॉबी' की शूटिंग गुलमर्ग और पहलगाम में हुई थी। 'रॉकस्टार', 'हाइवे', 'बजरंगी भाईजान', 'राजी', 'ये जवानी, ये जवानी' आदि की शूटिंग भी राज्य के विभिन्न लोकेशन पर हुई है।

वर्ष 1970 और 1980 के दशक में अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों का भी कश्मीर ने मन मोहा और 1983 में बिल मूरे की फिल्म 'रोजर्स एज' और ब्रिटिश फिल्म 'द क्लाइम्ब' की शूटिंग 1986 में हुई। 'राइडिंग सोलो टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड', लिविंग इन इमर्जेन्सी, हाइवेस्ट पास जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की शूटिंग भी घाटी के विभिन्न इलाकों में हुई। जर्मनी की फिल्म 'एस्केप फ्रॉम तिब्बत', ब्राजील की फिल्म 'बॉलीवुड ड्रीम', रूस की फिल्म 'द फॉल' की शूटिंग भी जम्मू कश्मीर में हुई और यहाँ की लोकेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही गई।

जम्मू कश्मीर में अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है कि पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। यह रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम भी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पर्यटन के साथ-साथ फिल्म उद्योग के लिए नया इतिहास लिख रहा है। जी-20 की बैठक के दौरान भी इस डिजिटल क्रांति को महसूस किया गया, जहाँ इंटरनेट मीडिया पर छोटे फोटो और वीडियो के माध्यम से जीवन सुगमता की नई चेतना सहज रूप में परिलक्षित हो रही थी। जाहिर सी बात है कि विकास की नई राह के कारण जम्मू कश्मीर आज देश दुनिया का सबसे लोकप्रिय फिल्म स्थल बन रहा है और राज्य के विभिन्न स्थान फिल्मकारों को आकर्षित कर आमंत्रित कर रहे हैं।

जम्मू कश्मीर फिल्म नीति-2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने पर फिल्म शूटिंग की मंजूरी दो से चार हफ्तों में फिल्मकारों को मिल रही है और आर्थिक मदद के साथ-साथ संसाधन भी मुहैया कराये जा रहे हैं। यही कारण है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहते हैं, "लगभग चार दशक के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और बॉलीवुड के रिश्ते को बहाल किया गया है। वर्ष 2021 में फिल्म क्षेत्र से संबंधित निवेश को ज्यादा आकर्षित करने के साथ ही जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे लोकप्रिय फिल्म शूटिंग स्थल बना है।" वहीं, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि कश्मीर समेत पूरे देश में फिल्म निर्माताओं के लिए हर तरह के शूटिंग स्थल हैं। जम्मू कश्मीर में देश का नंबर एक फिल्म पर्यटन स्थल बनने की पूरी संभावना है। देश की सर्वश्रेष्ठ रामोजी फिल्म सिटी मेरे गृह प्रदेश तेलंगाना में है और जम्मू कश्मीर के हर पर्यटनस्थल पर एक फिल्म सिटी होने की इच्छा उनकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का भी मानना है कि कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत वादियां सब कुछ हैं। हालात में बदलाव के साथ ही कश्मीर घाटी एक बार फिर देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। फिल्म जगत और कश्मीर का जो संबंध टूटा है,

उसे फिर से मजबूत और जीवंत बनाने का मौका है।

जी-20 देशों की बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माण को लेकर काफी बातचीत हुई और यह संदेश पूरी दुनिया को दी गई कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मकार राज्य के विभिन्न लोकेशन पर शूटिंग करें। दक्षिण भारतीय फिल्म सिनेमा के सुपर स्टार और नाटु-नाटु गीत से पूरी दुनिया में छाये रामचरण ने भी कहा कि कश्मीर ऐसी खूबसूरत जगह है जिसे आसानी से बयां नहीं किया जा सकता है। यह किसी को भी मोह लेता है और यहाँ खिंचा चला आता है। कश्मीर हमेशा से ही सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। मेरे पिता ने गुलमर्ग और सोनमर्ग में कई फिल्मों की शूटिंग की है। यहाँ मैंने खुद अपनी एक फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया है।

जी-20 सम्मलेन में भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी कहा कि कश्मीर फिल्म शूटिंग के लिहाज से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। राज्य में सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर है और रोमांटिक फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बढ़कर कोई दूसरी जगह नहीं है। वहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि कश्मीर में बीते कुछ समय के दौरान 400 फिल्मों, टीवी सीरियल और विज्ञापनों की शूटिंग की अनुमति दी गई है। यह प्रो-एक्टिव इकोसिस्टम के जरिये संभव हो पाया है। संबंधित अधिकारी फिल्मों की शूटिंग के लिए संबंधित लोगों को आवश्यक मदद प्रदान करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय फिल्म यूनिटों के लिए वीजा संबंधी औपचारिकताओं में भी सहयोग करते हैं।

जम्मू कश्मीर सूचना विभाग के निदेशक मिंगा शेरपा ने भी जी-20 सम्मलेन के दौरान विदेशी मेहमानों को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत विरासत और यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन की संभावनाओं से अवगत कराया था। उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर सरकार ने फिल्मों की शूटिंग के लिए विशेष स्थल विकसित किये हैं। राज्य सरकार ने राज्य के 300 ऐसे स्थलों की सूची सार्वजनिक की है। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है। इससे फिल्म निर्माताओं को अलग-अलग विभागों से इजाजत लेने के लिए नहीं भटकना पड़ता। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की पहाड़ियां, जंगल और यहाँ की झीलों के इर्द-गिर्द फिल्म शूटिंग की संभावनाएं हैं।

बहरहाल, जम्मू कश्मीर में जिस तरह चौतरफा विकास राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और आतंकवाद व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा रहा है, ऐसे में यह भारत के मानचित्र की नई तस्वीर सामने लाने में सक्षम हो रहा है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग की लोकेशन दुनियाभर में चर्चित हैं पर प्रदेश सरकार नए ऐसे स्थलों का विकास कर रही है। यदि राज्य के हालात बेहतर होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब फिल्म शूटिंग से लेकर फिल्म निर्माण तक के लिए यह दुनिया भर के फिल्मकारों के आश्रय स्थल के रूप में सामने आएगा।



## पत्रकारिता जगत में हलचल



**मालिनी पार्थसारथी-** जानी-मानी पत्रकार मालिनी पार्थसारथी ने 'द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्रा. लि.' (THGPPL) के बोर्ड से इस्तीफा दे

दिया है। इस बारे में मालिनी पार्थसारथी ने एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में पार्थसारथी ने लिखा है, 'हिंदू ग्रुप में चेयरपर्सन के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके साथ ही मैंने इसके बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे संपादकीय विचारों को समूह में उचित स्थान नहीं मिल रहा था। चेयरपर्सन और डायरेक्टर (एडिटोरियल स्ट्रैटेजी) के रूप में मेरा पूरा प्रयास यह सुनिश्चित करना था कि हिंदू समूह स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की अपनी विरासत को पुनर्जीवित करे।'



**तुषार श्रीवास्तव-** पत्रकार तुषार श्रीवास्तव ने वरिष्ठ टीवी पत्रकार शमशेर सिंह के नेतृत्व में जल्द लॉन्च होने जा रहे हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया डेली लाइव' जॉइन कर लिया है। तुषार

श्रीवास्तव ने बताया कि यहां वह उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और लखनऊ व दिल्ली से अपना कामकाज संभालेंगे।



**आयुष सूर्यवंशी-** युवा टीवी पत्रकार आयुष सूर्यवंशी ने हिंदी न्यूज चैनल 'भारत24' के साथ मीडिया में अपने नए सफर की शुरुआत की है।

आयुष सूर्यवंशी ने बताया कि उन्होंने यहां पर बतौर एंकर/प्रड्यूसर जॉइन किया है। उनको मीडिया में काम करने का करीब छह साल का अनुभव है। 'भारत24' से पहले वह 'न्यूज नेशन नेटवर्क' के रीजनल चैनल न्यूज स्टेट यूके/यूपी में कार्यरत थे।

**प्रत्यूष खरे-** जाने-माने पत्रकार और सीनियर न्यूज एंकर प्रत्यूष खरे ने मीडिया में अपने नए सफर की शुरुआत कर दी है। प्रत्यूष खरे ने बताया कि वरिष्ठ टीवी



पत्रकार शमशेर सिंह के नेतृत्व में जल्द ही लॉन्च होने जा रहे हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया डेली लाइव' में जॉइन कर लिया है। यहां वह डिप्टी एडिटर/सीनियर एंकर के पद पर अपनी जिम्मेदारी

संभालेंगे।



**प्रांशु मिश्रा-** अंग्रेजी न्यूज चैनल 'सीएनएन न्यूज18' के यूपी ब्यूरो चीफ प्रांशु मिश्रा ने यहां से बाय बोल दिया है। वह करीब सात साल से लखनऊ में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।

विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, प्रांशु मिश्रा जल्द ही मीडिया में अपने नए सफर की शुरुआत 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से करने जा रहे हैं। यहां वह बतौर रेजिडेंट एडिटर (यूपी) अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे और लखनऊ से अपना कामकाज देखेंगे।



**रुबिका लियाकत-** देश के प्रमुख न्यूज नेटवर्क में शुमार 'एबीपी नेटवर्क' को छोड़कर वरिष्ठ पत्रकार रुबिका लियाकत भारत 24 से जुड़ गई है, बतौर Vice President

रुबिका का ये सफर नए भारत के नए कश्मीर से शुरु हुआ, Bharat 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डा. जगदीश चंद्र और भारत 24 की सीनियर टीम की मौजूदगी में रुबिका लियाकत संस्थान के साथ जुड़ीं।



**जिया शर्मा-** अपनी बेहतरीन पेशकश, शानदार आवाज और अनोखी शैली के लिए पहचानी जाने वाली न्यूज एंकर जिया शर्मा ने हिंदी न्यूज चैनल 'एबीपी न्यूज' से इस्तीफा

दे दिया है। वह करीब दो साल से यहां अपनी जिम्मेदारी निभा रही थीं और एबीपी न्यूज के शो 'नमस्ते भारत' की एंकरिंग करती थीं। जिया शर्मा ने अपने इस्तीफे की पुष्टि



की है। जिया शर्मा के अनुसार, वह जल्द ही अपनी नई पारी की शुरुआत करेगी और फिर उस चैनल के नाम का खुलासा करेगी।



**अमित सिंह चौहान**- टीवी पत्रकार अमित सिंह चौहान ने नई पारी का आगाज कर दिया है। वह एक बार फिर शमशेर सिंह एंड टीम का हिस्सा बन गए हैं। अमित सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने शमशेर सिंह के

नेतृत्व में जल्द लॉन्च होने जा रहे हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया डेली लाइव' में बतौर एसोसिएट एग्जिक्यूटिव प्रड्यूसर जॉइन किया है। इससे पहले अमित 'रिपब्लिक भारत' में 8 बजे के शो 'अंदर की खबर' का अहम हिस्सा थे। इससे पहले वह 'भारत एक्सप्रेस', 'जी हिंदुस्तान', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'जी न्यूज' और 'न्यूज नेशन' में अपनी भूमिका निभा चुके हैं।



**घनश्याम उपाध्याय**- पत्रकार घनश्याम उपाध्याय ने पिछले दिनों 'एमएच1' न्यूज चैनल में अपनी पारी को विराम देने के बाद मीडिया में अपनी नई मंजिल तलाश ली है।

उन्होंने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ टीवी पत्रकार शमशेर सिंह के नेतृत्व में जल्द ही लॉन्च होने जा रहे हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया डेली लाइव' में जॉइन कर लिया है। यहां उन्होंने सीनियर न्यूज एंकर के पद पर जॉइन किया है।



**विवेक शांडिल्य**- युवा पत्रकार विवेक शांडिल्य भी अब वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह के नेतृत्व में जल्द लॉन्च होने वाली हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया डेली लाइव' में शामिल

हो गए हैं। विवेक शांडिल्य ने बताया कि यहां पर उन्होंने बतौर डिप्टी एडिटर/एंकर जॉइन किया है। इससे पहले विवेक शांडिल्य 'इंडिया टीवी' में करीब एक साल से सीनियर एडिटर/एंकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। पूर्व में वह 'रिपब्लिक भारत' चैनल में भी

एंकर के तौर पर जुड़े रहे हैं।



**प्रभाकर कुमार**- 'भारत 24' में कार्यरत टीवी पत्रकार प्रभाकर कुमार ने चैनल को अलिवदा कह दिया है। वह यहां इवनिंग शिफ्ट इंचार्ज के तौर पर पिछले 9 महीने से कार्यरत थे।

प्रभाकर कुमार अपनी नई शुरुआत कहां से करेंगे, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। वो पिछले 15 वर्षों से मीडिया इंडस्ट्री में कार्यरत हैं और आजतक, इंडिया टीवी, जी मीडिया, एबीपी नेटवर्क जैसे संस्थानों में अपना योगदान दे चुके हैं।



**अदिति अवस्थी**- जानी-मानी न्यूज एंकर अदिति अवस्थी ने नई मंजिल तलाश ली है। अदिति अवस्थी ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह के नेतृत्व में जल्द लॉन्च

होने जा रहे हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया डेली' में जॉइन कर लिया है। यहां वह बतौर डिप्टी एडिटर कम सीनियर एंकर अपनी भूमिका निभाएंगी।



**सुरभि तिवारी**- युवा पत्रकार सुरभि तिवारी ने मीडिया में अपनी नई मंजिल तलाश ली है। सुरभि तिवारी ने बताया कि वह एक बार फिर अपने पुराने बॉस शमशेर सिंह

के नेतृत्व में जल्द लॉन्च होने जा रहे हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया डेली लाइव' के साथ नए सफर की शुरुआत करने जा रही हैं। यहां उन्होंने बतौर एंकर/प्रड्यूसर जॉइन किया है। बता दें कि सुरभि तिवारी ने पिछले दिनों हिंदी न्यूज चैनल 'भारत24' में अपनी पारी को विराम दे दिया था। यहां वह एंकर/प्रड्यूसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थीं।



संकलन : मोहित कुमार (प्रोड्यूसर, न्यूज 24)





## मुख्य समाचार

- ☞ **26 मई** : उत्तर प्रदेश सरकार का गौसंवर्धन में प्रेरणादायी प्रयास, अब तक 11 लाख 57 हजार 204 निराश्रित गोवंश को संरक्षण प्रदान किया।
- ☞ हरिद्वार में हुई विश्व हिन्दू परिषद की केन्द्रीय मार्गदर्शक मण्डल की बैठक, देश में सख्त धर्मांतरण कानून लाया जाए और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए - विहिप।
- ☞ **27 मई** : विहिप की साध्वी गोष्ठी में साध्वियों से किया गया कन्वर्जन और लव जिहाद को लेकर जन जागरण करने का आह्वान।
- ☞ **28 मई** : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुबह रायसीना हिल्स में स्थापित संसद के नए भवन का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नए भवन में पवित्र राजदंड 'सेंगोल' को स्थापित किया।
- ☞ **29 मई** : अंतरिक्ष में इसरो की एक और छलांग, भारत की आत्मनिर्भर उड़ान, NVS-01 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग।
- ☞ **30 मई** : भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए काठमांडू में आयोजित कावा सेन्ट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीत लिया।
- ☞ **1 जून** : एनआईए ने कश्मीर में तीन स्थानों पर नए बने आतंकी संगठनों पर छापेमारी की। आपत्तिजनक सामग्री सहित कई डिजिटल उपकरण किए जब्त।
- ☞ **2 जून** : नागपुर के रेशिमबाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग समापन समारोह में अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामीजी ने कहा कि संघ यानी सेवा और समर्पण, संघ यानी हिन्दुत्व, हिन्दुत्व यानी राष्ट्रियता।
- ☞ **3 जून** : ओडिशा रेल हादसा : प्रशासन से पहले पहुंचे संघ के स्वयंसेवक, बचाव कार्य से लेकर मानवीय दायित्व में जुटे रहे, स्वयंसेवकों ने रक्त दान भी किया।
- ☞ **4 जून** : माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
- ☞ **5 जून** : सीबीआई ने ओडिशा रेल दुर्घटना के सिलसिले में मामला दर्ज किया। बाहानगा में दुर्घटनास्थल पर जांच शुरू की।
- ☞ **6 जून** : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय मूल के सूरीनाम के छठी पीढ़ी के नागरिकों को ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया कार्ड्स देने की घोषणा की।
- ☞ **7 जून** : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा विपणन सत्र के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की।
- ☞ **8 जून** : भारत ने ओडिशा तट से अग्नि प्राइम बेलेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- ☞ **9 जून** : भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान की खाड़ी में तीन देशों का पहला नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा।
- ☞ **10 जून** : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी में कहा कि भारत सरकार विदेशों में भी हिन्दू मंदिरों का कायाकल्प करा रही है। आबूधाबी में बन रहा मंदिर इस साल के अंत में होगा पूरा। बहरीन और फ्रांस में मंदिर निर्माण की अनुमति मिल गई, न्यूयार्क में भी मंदिर निर्माण के प्रयास जारी।
- ☞ **11 जून** : लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर पेरिस में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में तीसरे स्थान पर रहे।
- ☞ **12 जून** : भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 4 जुलाई को होंगे।
- ☞ **13 जून** : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 70 हजार नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, कहा- भारत एक दशक पहले की तुलना में अधिक स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है।
- ☞ **14 जून** : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों के कन्वर्जन कराने के आरोपी खान शाहनवाज उर्फ बद्दो को 14 दिन की न्यायिक



- हिरासत में भेजा, पाकिस्तान कनेक्शन पर पूछताछ जारी।
- ☞ 15 जून : भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए।
  - ☞ नित्य गंगा आरती करने वाले विमु ने पास की नीट परीक्षा, सीएम योगी बोले-ये संस्कारित-अनुशासित जीवन शैली का प्रतिफल।
  - ☞ 16 जून : चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में पहुँचा, राजस्थान के कई जिलों में बहुत तेज वर्षा होने की आशंका, मौसम विभाग ने इसकी तीव्रता कम बताई।
  - ☞ देश में कोयले का कुल भंडार 44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 110 मिलियन टन हुआ।
  - ☞ 17 जून : उत्तराखंड : हिंदू लड़कियों के गुमशुदा और अपहरण मामलों की फाइलें फिर से खुलेंगी, धर्मांतरण कानून के तहत होगी कार्रवाई।
  - ☞ 18 जून : कांवड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी : 12 फीट से ऊपर कांवड़ की इजाजत नहीं, पहचान पत्र लाना अनिवार्य।
  - ☞ 19 जून : वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार की सम्मान राशि नहीं लेगा गीता प्रेस
  - ☞ 20 जून : उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के पति-पत्नी ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, अयोध्या, मथुरा घूमने के बाद हुआ हृदय परिवर्तन, बरेली में कृष्ण भक्त शहनाज ने आरोही बनकर अपनाया सनातन धर्म, शहनाज को शौहर ने दे दिया था तलाक।
  - ☞ 21 जून : ओडिशा के जगन्नाथ पुरी की रथयात्रा में सेवाकार्य में दिन-रात जुटे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1100 स्वयंसेवक।
  - ☞ 22 जून : मेरठ : बेगम पुल अब भारत माता चौक तो ईलज चौराहा माधव चौक के नाम से जाना जाएगा। देवबंद में आबकारी रोड का नाम सरदार पटेल मार्ग और गाड़ो वाले चौक का नाम सरदार भगत सिंह चौक कर दिया गया है।
  - ☞ 23 जून : जम्मू-कश्मीर : कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, घुसपैठ की कोशिश कर रहे चार आतंकवादी डेर।

## अंतर्राष्ट्रीय समाचार

- ◆ वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट 'आईएनएस कृपाण' उपहार में देगा भारत।
- ◆ न्यूयॉर्क में अब दिवाली पर मिलेगी आधिकारिक छुट्टी, विधानमंडल में पास हुआ बिल।
- ◆ अमेरिकी संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चारों से हुई पहले हिंदू-अमेरिकन सम्मेलन की शुरुआत, भगवद्गीता का भी हुआ जिक्र।
- ◆ सिंगापुर के प्राचीन हिंदू मंदिर श्री थेंडायुयपानी मंदिर में 12,000 हिंदू भक्तों ने अभिषेक समारोह में भाग लिया, सरकार ने 2014 में इस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था।
- ◆ एक दशक से भी कम समय में बदला भारत, 2013 से अब तक काफ़ी अलग मॉर्गन स्टेनली रिपोर्ट।
- ◆ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार' से सम्मानित किया गया।
- ◆ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष अधिकारी, कर्ट कैपबेल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जिस स्तर का विश्वास और भरोसा विकसित हुआ है, वह एक दशक पहले नहीं था।
- ◆ बांग्लादेश में चल रहा 103 साल पुराना संस्कृत विद्यालय, यहां मुस्लिम छात्र भी करते हैं मंत्रोच्चार।
- ◆ व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा, 'भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। कोई भी दिल्ली जाकर यह देख सकता है'।
- ◆ पाकिस्तान के मशहूर इन्फ्लुएंसर शायन अली ने सनातन धर्म में घर वापसी की। ट्विटर पर जानकारी साझा कर स्वयं को हिंदू घोषित किया।
- ◆ अमेरिकी कांग्रेस समिति ने सिफारिश कर कहा- भारत को बनाया जाए नाटो प्लस का हिस्सा, भारत को इसमें शामिल किए जाने से नाटो प्लस को मजबूती मिलेगी।
- ◆ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बना विश्व रिकॉर्ड, 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग सत्र का नेतृत्व किया।
- ◆ अमेरिकी संसद में छाप प्रधानमंत्री, मोदी-मोदी के नारों से गुंजा संसद, पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत विकास करता है तो न केवल देशवासियों का इससे फायदा होता है, बल्कि पूरे विश्व का इससे विकास होता है।



# क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है?
  - आईआईएससी बेंगलुरु
  - आईआईटी मद्रास
  - अमृता विश्वविद्यालय
  - आईआईटी खड़गपुर
- 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है?
  - पंजाब
  - नई दिल्ली
  - अहमदाबाद
  - मुंबई
- संसद के नए भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं?
  - 888
  - 552
  - 245
  - 550
- भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है?
  - सांची के स्तम्भ
  - प्रयागराज के स्तम्भ
  - सारनाथ के स्तम्भ
  - लुम्बिनी के स्तम्भ
- संसद के नए भवन का आकार कैसा है?
  - गोल
  - त्रिकोणीय
  - षट्कोण
  - चौकोर
- निम्न में से किसने वैदिक काल में विंध्याचल को पार किया और दक्षिण भारत का रुख किया?
  - ऋषि कपिल
  - ऋषि अगस्त्य
  - ऋषि गौतम
  - ऋषि अत्रि
- भावार्थ रामायण किसने लिखी थी?
  - माघव कंडाली
  - एकनाथ
  - कृतिबास
  - बुद्ध रेड्डी
- गायत्री मंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
  - रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है।
  - गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं।
  - यजुर्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है।
  - केवल A और B सही हैं
- किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है?
  - अभिज्ञान
  - शाकुन्तलम
  - पंचतंत्र
  - कथासरित सागर
- राष्ट्रीय गान के लिए निर्दिष्ट समय सीमा क्या है ?
  - 48 सेकंड
  - 50 सेकंड
  - 52 सेकंड
  - 54 सेकंड

उत्तर : 1- b, 2- b, 3 - a 4 - c, 5 - b, 6 - b, 7- b, 8 - d, 9 - c, 10 - c



## प्रेरणा विचार

प्रिय पाठकगण आपको यह जानकर हर्ष होगा कि प्रेरणा विचार मासिक पत्रिका द्वारा 25 अक्टूबर 2023 से 5 नवम्बर 2023 के बीच पाठकों के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसमें जुलाई 2023 से अक्टूबर 2023 (4 माह) की पत्रिकाओं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास जुलाई 2023 से प्रेरणा विचार पत्रिका का प्रत्येक अंक पहुंचेगा। जिसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा तथा उन्हीं अंकों में से पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा दो वर्गों में आयोजित की जायेंगी।

◆ वर्ग 1- विद्यार्थी

◆ वर्ग-2- सामान्य

☞ सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता पत्र (ई-प्रमाण पत्र) मिलेगा।

☞ दोनों वर्गों के प्रथम तीन स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह दिया जाएगा।

पाठकगण प्रेरणा विचार पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से हमारी ई-मेल आईडी (prenavichar@gmail.com) या वाट्सएप नम्बर (9354133754) पर भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।





## **NIRALA WORLD RESIDENCY PRIVATE LIMITED**

Corp. Office: H-61, 1st Floor, Sec-63, Noida (U.P.) 201301 | Site Office : GH-03A, Sector-2, Gr. Noida (West), U.P.

For Sales enquiries: 9212131476

Tel.: 0120-4823000, Email: [sales@niralaworld.com](mailto:sales@niralaworld.com), Web.: [www.niralaworld.com](http://www.niralaworld.com)